● वर्ष-4
● अंक-10
रायपुर, गुरुवार 22 अगस्त 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmail.com

पेज-6›› सौन्दर्य के संसार में खूबसूरत...

नरेंद्र मोदी पोलैंड यात्रा पर

45 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा

पोलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय पोलैंड यात्रा पर राजधानी वारसॉ पहुंच गए हैं। पीएम मोदी 21 और 22 अगस्त को यूरोपीय देश की दो दिवसीय यात्रा पर हैं। इसके बाद 23 अगस्त को पीएम मोदी युद्धग्रस्त यूक्रेन का दौरा करेंगे। पोलैंड मध्य यूरोप में भारत का अहम व्यापारिक साझेदार है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह 45 साल बाद पहली पोलैंड यात्रा है। वारसॉ पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का स्वागत किया।

पोलैंड यात्रा का कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 22 अगस्त तक पोलैंड की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा साझा किए कार्यक्रम के अनुसार, प्रधानमंत्री का पोलैंड की राजधानी वारसॉ में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। वह राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इन बैठकों का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को पुनर्जीवित करने का एक अवसर बनना है। प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड में भारतीय प्रवासियों की एक सभा को भी संबोधित करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री की यह यात्रा पोलैंड और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ पर हो रही है। किसी भारतीय पीएम की पोलैंड की पिछली यात्रा 45 साल पहले 1979 में हुई थी। उस वक्त मोरारजी देसाई पोलैंड आए थे। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने भी इस यूरोपीय देश का दौरा किया था।

पोलिस प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क गुरुवार सुबह 10 बजे (स्थानीय समयानुसार) पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। वहीं गुरुवार दोपहर को पोलिश राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। यह बैठक गुरुवार को बेल्वेडर में होगी। बेल्वेडर पोलिश राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास है और साथ ही एक राजकीय अतिथि गृह भी है। पीएम मोदी इस दो दिवसीय यात्रा के दौरान ज्यादातर समय राजधानी वारसॉ में बिताएंगे। वारसॉ पहुंचने के बाद पीएम मोदी सबसे पहले तीन स्मारकों पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पोलैंड में भारतीय राजदूत नगमा मोहम्मद मलिक ने कहा कि वह इन तीनों स्मारकों पर श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे।

प्रधानमंत्री मोदी जामनगर और कोल्हापुर के महाराजाओं के स्मारकों का दौरा करेंगे। जामनगर और कोल्हापुर के इन महाराजाओं ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हजारों पोलिश शरणार्थियों को आश्रय दिया था। पीएम मोदी सैनिक स्मारक और बैटल ऑफ मोंटे कैसिनो स्मारक का भी दौरा करेंगे, जिसमें दोनों देशों ने भाग लिया था। पीएम मोदी को पोलैंड में उच्चतम स्तर पर बैठकें करनी हैं। इस यात्रा में आर्थिक पहलू भी शामिल होने की उम्मीद है।

दौरे का उद्देश्य

दो दिवसीय यात्रा का मुख्य उद्देश्य रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और पोलैंड और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा करना है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यात्रा के दौरान मोदी को द्विपक्षीय संबंधों को नवीनीकृत और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना है। कई वर्षों के बाद, भारत ने पोलैंड के साथ रणनीतिक सहयोग के बढ़ते महत्व पर जोर देते हुए वारसॉ में अपना पहला सैन्य अताशे नियुक्त किया था। सैन्य अताशे या डिफेंस अताशे सैन्य एक्सपर्ट होते हैं जो दूतावास से जुड़े होते हैं।

राम माधव फिर निकले भाजपा के मिशन कश्मीर पर

जी किशन रेड्डी बनाए गए चुनाव प्रभारी

नई दिल्ली। आरएसएस पदाधिकारी और भाजपा के पूर्व महासचिव राम माधव सक्रिय राजनीति में लौट आए। पार्टी ने उन्हें केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया है। भाजपा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दोनों नेताओं को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। चुनावी पंडितों की मानें तो आरएसएस के दबाव के चलते ही वह सक्रिय राजनीति में लौटे हैं। यह असामान्य है कि दो नेताओं को एक साथ चुनाव प्रभारी बनाया जाए, क्योंकि आम तौर पर एक प्रभारी के साथ एक या उससे ज़्यादा सह-प्रभारी होते हैं। 2014-2020 के बीच बीजेपी के एक प्रमुख संगठनात्मक नेता के तौर पर माधव पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य की राजनीति से गहराई से जुड़े रहे और 2014 के विधानसभा चुनावों में त्रिशंकु जनादेश आने के बाद 2015 में पीडीपी के साथ इसके अप्रत्याशित गठबंधन में उनकी अहम भूमिका देखी गई। 2018 में जब भाजपा ने पीडीपी से नाता तोड़ा था, तब वह प्रभारी थे। माधव को वापस लाने का भाजपा नेतृत्व का फैसला इस बात को रेखांकित करता है कि वह केंद्र शासित प्रदेश की राजनीति में पार्टी के लिए उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं, जो दोष रेखाओं और विवादित आख्यानों से भरी है, और एक व्यापक विषय से रहित है। सूत्रों ने कहा कि नियुक्ति से आरएसएस की संभावित भूमिका का भी संकेत मिलता है।

माधव को 2020 में भाजपा महासचिव के पद से हटा दिया गया था और 2021 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में वापस आ गए और उन्हें हिंदुत्व संगठन का कार्यकारी सदस्य बना दिया गया। वह थिंक टैंक इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं और मीडिया में राय पृष्ठों में नियमित योगदान देते हैं। भाजपा में अपने पिछले कार्यकाल में, वह अधिक दिखाई देने वाले पार्टी महासचिवों में से एक थे, जिन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसके विस्तार अभियान का भी नेतृत्व किया था।

कानून में बदलाव वक्त और वक्फ दोनों की जरूरत

'टच मी नॉट' की राजनीति से आना होगा बाहरः नकवी

नई दिल्ली। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर जारी राजनीतिक विवाद के बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यह विधेयक समय की मांग है। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गुरुवार (22 अगस्त) को पहली बार बैठक करने की तैयारी कर रही है, जिसमें हाल ही में संपन्न संसद सत्र के दौरान मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए वक्फ (संशोधन) विधेयक पर चर्चा की जाएगी। यह विधेयक भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है और पार्टी के रणनीतिकार चाहते हैं कि इसे संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पारित कर दिया जाए। हालांकि, बहुत कुछ जेपीसी की रिपोर्ट पर भी निर्भर करता है। भाजपा को न केवल विपक्षी दलों को साथ लाना है, बल्कि चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान जैसे सहयोगियों को भी विधेयक का समर्थन करने के लिए राजी करना है। नकवी ने कहा कि इस पूरी व्यवस्था (वक्फ बोर्ड की) को छूओ मत की राजनीति से बाहर आना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यह विधेयक लेकर आई है। विपक्षी दलों और कुछ सहयोगी दलों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए नकवी ने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि वक्फ कानूनों में संशोधन किया जा रहा है, पहले भी संशोधन किए गए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान संशोधन किए गए थे। सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विस्तार से चर्चा, विचार-विमर्श और विश्लेषण होना चाहिए, इसीलिए इसे जेपीसी के पास भेजा गया है। जेपीसी एक संवैधानिक संस्था है और इसकी बैठकों में इस विधेयक पर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल के पास जो भी तर्क होंगे, वे जेपीसी की बैठकों में सामने आएंगे। विधेयक को सांप्रदायिक रंग देने के 'प्रयासों' का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि इसे लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं और भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए इस पर गहन चर्चा के लिए इसे जेपीसी के पास भेजा गया है। उन्होंने कहा कि यह संशोधन समय की मांग है और यह नहीं माना जाना चाहिए कि किसी पर हमला किया जा रहा है या यह विधेयक किसी के खिलाफ है।

रायपुर। उत्तर अमेरिका में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित इंडिया डे परेड के उद्घाटन समारोह में नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन (नाचा) सीएटल चैप्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व कर लोगों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी है7 दूतावास के गठन के बाद पहली बार आयोजित इस कार्यक्रम में नाचा के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति का प्रदर्शन किया। सीएटल के कार्यक्रम में भाग लेने के अलावा, नाचा के सदस्यों ने डेट्रॉइट, शिकागो, लंदन और कैलिफोर्निया में भी आयोजित इंडिया डे परेड में भी सक्रिय रूप से भाग लिया।

चंपई सोरेन ने नई पार्टी बनाने के दिए संकेत

नई दिल्ली। भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम नेता चंपई सोरेन ने आज बड़े संकेत दिए हैं। चंपई सोरेन ने साफ तौर पर कहा कि मैं राजनीति से संन्यास नहीं लूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने जो नया अध्याय शुरू किया है, उसमें नए संगठन को मजबूत करूंगा और अगर रास्ते में कोई अच्छा दोस्त मिला तो उस दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए जनता और राज्य की सेवा करूंगा। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में सब कुछ साफ हो जाएगा।

इससे पहले चंपई सोरेन ने भाजपा में शामिल होने की खबरों को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई। मैं यहां (दिल्ली) किसी निजी काम से आया था। मैं उनसे (भाजपा नेता से) मिलना नहीं चाहता था। भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि यह सब कौन कह रहा है? झारखंड इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को कहा कि चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने की संभावनाओं को लेकर उनके साथ अभी कोई बातचीत नहीं हुई है।

प्रमुख समाचार

डॉक्टरों पर हिंसाः सुको के आदेश पर टास्क फोर्स गठित

नई दिल्ली। देश में डॉक्टरों की हड़ताल के बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 14 सदस्यों की इस समिति की घोषणा की है जिसमें कैबिनेट से लेकर गृह सचिव तक शामिल हैं। यह समिति तीन सप्ताह के दौरान अपनी अंतरिम रिपोर्ट देगी जबकि अंतिम रिपोर्ट के लिए दो महीने का वक्त दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के अलावा अस्पतालों में बुनियादी विकास, सामाजिक कार्यकर्ताओं की तैनाती और अस्पताल परिसर में पुलिस चौकी की स्थापना जैसे मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाएगा। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय टास्क फोर्स (एनटीएफ) चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा, कामकाजी परिस्थितियों और भलाई के अलावा अन्य संबंधित मामलों के समाधान को लेकर प्रभावी सिफारिशें तैयार करेगा। मंत्रालय का कहना है कि चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम और सुरक्षित कार्य स्थल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स से दो चरणों में सिफारिशें तैयार करने के लिए कहा है।

टीएमसी नेता घोष ने पुलवामा हमले से की कोलकाता रेप कांड की तुलना

कोलकाता। कोलकाता में विरोध प्रदर्शन जारी है और आरजी कर अस्पताल में बलात्कार और हत्या मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस आलोचनाओं का सामना कर रही है, वहीं पार्टी नेता कुणाल घोष ने स्थिति की तुलना 2019 के पुलवामा आतंकी हमले से की है। उन्होंने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से काम पर लौटने का भी आग्रह किया। कोलकाता के एक अस्पताल में 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या के बाद डॉक्टरों ने 10वें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रखा। कुणाल घोष ने अपनी पोस्ट में, जो बंगाली में थी, लगभग यही कहा, मेरे पास डॉक्टरों से एक सवाल और अनुरोध है कि वे काम पर लौट आएं। पुलवामा की घटना में अभी भी न्याय नहीं हुआ है। इसलिए, अगर सैनिक पुलवामा में कहते हैं कि हमें न्याय चाहिए... तो अगर वे सीमा छोड़कर विरोध में बैठेंगे तो यह कैसे सामने आएगा? पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पतालों में बुधवार को स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहीं, क्योंकि जूनियर डॉक्टरों ने आरजी कर अस्पताल में एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु के कथित बलात्कार और हत्या के विरोध में लगातार 13वें दिन भी अपना काम बंद रखा।

खत्म हो गई अदावत! मौर्य ने फिर की योगी की तारीफ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर पिछले दिनों एक खबर जबरदस्त तरीके से उफान पर थी। खबर यह थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य हाल के दिनों में देखें तो जबरदस्त तरीके से योगी आदित्यनाथ की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं। आज एक बार फिर से उन्होंने जबरदस्त तरीके से योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि योगी जी के रहते राष्ट्रभक्ति और रामभक्ति से कोई समझौता नहीं होगा। इतना ही नहीं, केशव मौर्य ने तो योगी के शासन को पूरी तरीके से सुशासन बताया और कहा कि वह बाबूजी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। दरअसल, भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित तमाम नेता मौजूद रहे। इसी दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की।

आंध्र प्रदेश की दवा फैक्टरी में धमाका, 15 लोगों की मौत

अनकापल्ली। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में बुधवार को दवा बनाने वाली एक फैक्टरी में विस्फोट से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, हादसे के समय यूनिट में फंसे 13 लोगों को बचा लिया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अच्युतपुरम फार्मा कंपनी दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए है। बुधवार के हादसे के संबंध में अनकापल्ली जिलाधिकारी विजय कृष्णन ने बताया, जिले के अचुटापुरम स्थित एसेंशिया एडवांस्ड साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड में दोपहर 2:15 बजे आग लग गई। फैक्टरी में दो शिफ्ट में 381 कर्मचारी काम करते हैं। विस्फोट लंच के समय हुआ। इसलिए, कर्मचारियों की उपस्थिति कम थी। उन्होंने कहा कि धमाका बिजली से संबंधित होने का संदेह है। 40 घायल लोगों को अनकापल्ली और अचुटापुरम के कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं इस हादसे की सूचना पर अग्निशमन विभाग, छह दमकल गाड़ियों को मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान में लगा हुआ है। इस बीच, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कंपनी में लोगों की मौत पर दुख जताया है।

जाकिर पर कार्रवाई जरूर होगीः अनवर इब्राहिम

नई दिल्ली। मलेशियाई प्रधान मंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा है कि वह विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण के अनुरोध के संबंध में भारत से किसी भी सबूत के लिए तैयार हैं। इंडिया टुडे के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अनवर इब्राहिम ने हालांकि इस बात पर जोर दिया कि नाइक ने मलेशिया में भारत के खिलाफ कुछ भी विवादास्पद नहीं कहा है। जब तक जाकिर नाइक समस्याएं पैदा नहीं करता या सुरक्षा को खतरा नहीं पहुंचाता, हम इस मामले को शांत रहने देंगे। लेकिन हम कानून के तहत उसे प्रत्यर्पित करने के लिए भारत द्वारा दिए गए किसी भी सबूत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर सबूत मिलते हैं तो कार्रवाई जरूर करेंगे। मलेशियाई पीएम ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात के दौरान जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया था। जाकिर नाइक, जिनका जन्म मुंबई में हुआ था, नफरत फैलाने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बीच 2016 में भारत से भाग गए थे। इस्लामिक उपदेशक को पिछली महाथिर मोहम्मद सरकार द्वारा मलेशिया में स्थायी निवास की अनुमति दी गई थी, जिससे भारत को काफी निराशा हुई थी।

वर्तमान परिदृश्य में आरक्षण की आवश्यकता

चन्द्र शेखर गंगराड़े

भारत जब स्वतंत्र हुआ, उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्गों के लिए लोकसभा तथा विधान सभाओं में 10 वर्ष के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था ताकि उक्त संवर्ग के लोगों को भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा तथा विधान सभाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले लेकिन प्रथम 10 वर्षों की समाप्ति पर पुनः संविधान संशोधन द्वारा, उक्त अवधि को हर 10 वर्ष की समाप्ति पर आगामी 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता रहा है और अब तक इसमें 7 बार वृद्धि की गई है. पहली बार जब प्रावधान किया गया था, तब संविधान सभा के सदस्यों का यह मत रहा होगा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के सर्वांगीण उत्थान के लिए यह प्रावधान आवश्यक है. लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसको बढ़ाया जाना राजनैतिक मजबूरी है।

सन् 1950 में जब यह प्रावधान किया गया था, तब उक्त जाति के लोगों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति क्या थी और जब-जब इस अवधि में वृद्धि की गई है, तब-तब उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में क्या अंतर आया, कितनी प्रगति हुई, कितने लोगों की आर्थिक स्थिति में वृद्धि हुई, इसका कोई अध्ययन या अनुसंधान सरकारी स्तर पर हुआ होगा ऐसा मेरा मानना है और यदि उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार हुआ है तो इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि आरक्षण को किस सीमा तक, कितनी अवधि तक और किस स्वरूप में जारी रखना चाहिए और यदि कोई सुधार नहीं हुआ है तब तो उसे निरंतर जारी रखने में कोई दिक्कत नहीं है।

जब संविधान बना, उस समय अनुसूचित जाति एवं जनजाति में कौन-कौन सी जातियां शामिल होंगी, उसका उल्लेख एवं जाति को उक्त सूची में शामिल करने की प्रक्रिया का उल्लेख, संविधान के अनुच्छेद 341 में कर दिया गया था। जिस प्रकार लोकसभा एवं विधानसभाओं में उक्त जाति के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान, संविधान में किया गया, ठीक उसी प्रकार अनुच्छेद 15 (4) के तहत शासकीय सेवाओं में भी उन्हें पर्याप्त अवसर मिले इसलिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया. अनुसूचित जाति एवं जनजाति में वे जातियां शामिल की गई हैं, जो हजारों वर्षों में विभिन्न कारणों से सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से वंचित रहीं और इस कारण वे धीरे-धीरे विकास की ओर अग्रसर होने के बजाए पिछड़ती चली गई.

अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा, वर्ष 1979 में जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी, तब उन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान करने हेतु मंडल आयोग का गठन किया और मंडल आयोग की रिपोर्ट को विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने अगस्त, 1990 में लागू कर दिया. हालांकि संवैधानिक प्रावधान न होने के कारण लोकसभा एवं विधानसभाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्थान आरक्षित नहीं है लेकिन शासकीय सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए पूर्व में आरक्षित सीमा के अतिरिक्त थी.

अब सवाल यह उठता है कि जब देश को आजाद हुए 77 वर्ष हो गये हैं तो क्या जिन जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, उनके शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार हुआ है। संभवतः इसका उत्तर नहीं है क्योंकि आरक्षण का लाभ जाति को देखकर दिया जाता है न कि जिस व्यक्ति को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, उसके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर को देखकर. हो यह रहा है कि आरक्षण के कारण जिन लोगों को उसका लाभ मिल चुका है, उन्हें ही या उनकी पीढ़ियों को ही लगातार इसका लाभ मिल रहा है और जो वास्तव में उपेक्षित या पिछड़े हैं, उनके स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है।

यही कारण है कि अभी हाल ही में दिनांक 1 अगस्त, 2024 को उच्चतम न्यायालय की 7 जजों की संविधानपीठ ने 6:1 के बहुमत से अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण में जातियों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करने का अधिकार राज्यों को दे दिया. न्यायालय का यह भी मत था कि एक ही जाति आरक्षण का अधिक लाभ उठायेगी तो बाकी कमजोर जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा जबकि आरक्षण का मकसद वंचित वर्गों को आगे बढ़ाना है. अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति कोटे में क्रीमीलेयर लागू करने पर भी जोर दिया।

हालांकि उसका सभी राजनैतिक दलों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया है और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सांसदों ने इस संबंध में प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और प्रधानमंत्री जी ने भी इसे लागू न करने की घोषणा कर दी.

क्रीमीलेयर को लागू न करने के पीछे यह तर्क दिया कि संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण में क्रीमीलेयर का प्रावधान नहीं है। अब क्या केवल इस आधार पर कि संविधान में क्रीमीलेयर का प्रावधान नहीं है, आर्थिक रूप से अति वंचित दलितों के अधिकारों का हनन् नहीं होगा। लेकिन इससे उन लोगों को अवसर नहीं मिलेगा जिन्हें आरक्षण के कारण बार बार अवसर मिलता रहता है और वे लोग पुनः वंचित रह जाते हैं जो वास्तव में आरक्षण के हकदार हैं।

स्कूल में छत का प्लास्टर गिरने से चार बच्चे घायल, दो गंभीर

विधायक अनिला भेड़िया पहुंची अस्पताल

बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है यहां पर स्कूल के छठ का स्लैब गिरने से पांच बच्चे घायल हो गए हैं जिसमें से दो बच्चों को गंभीर चोट आई है। इस घटना के बाद से गांव में तनातनी का माहौल है, सभी ग्रामीण स्कूल पहुंचे हुए हैं वहीं बच्चों को जिला अस्पताल इलाज के लिए लाया गया है। घटना के बाद से जिले के शिक्षा विभाग समन्वयक प्राथमिक शाला निरीक्षण करने पहुंचे जहां पर उन्होंने शिक्षकों को फटकार लगाई और कहा कि अतिरिक्त कमरा शानदार बना है आपको उनमें कक्षाएं संचालित करनी चाहिए पूरा मामला प्राथमिक शाला कोरगुड़ा का है वहीं क्षेत्रीय विधायक अनिला भेड़िया घायल बच्चों की स्थिति देखने पहुंची जिला अस्पताल। बच्चों के बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों को दिए दिशानिर्देश,विधायक अनिला ने कहा स्कूल के मरम्मत करने वाले लापरवाह ठेकेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए।

आपको बता दें कि छत गिरने से घायल सभी बच्चे कक्षा पांचवी के बताए जा रहे हैं

घटना हुई उसके बाद उन्हें आपातकालीन वहां से तत्काल जिला चिकित्सालय ले जाया गया जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है वही पालक टीम भी मौके पर पहुंची हुई है क्योंकि सभी को अपने बच्चों से प्रेम है सभी पलकों का आरोप है कि व्यवस्थित कैमरा रहते हुए भी इस तरह जर्जर कमरों में बच्चों को बैठाया गया था।

छत गिरने की घटना के बाद स्कूल द्वारा शिक्षकों द्वारा यहां पर घटना घटित हुए कमरे में ताला लगा दिया गया है जिस कमरे में पहले ही ताला लगा देना चाहिए था उसे शायद घटना के बाद ताला लगाना ईश्वर इशारा करता है कि शिक्षकों को घटना घटित होने का इंतजार था आपको बता दें कि जब जिले के समन्वयक स्कूल में पहुंचे तो उन्होंने शिक्षकों को फटकार लगाई और कहा कि अब ऑफिस जहां संचालित कर रहे हैं वहां बच्चों को पढ़ने के लिए बैठाएं।

पूरे मामले में सिविल सर्जन आर के श्रीमाली ने बताया कि चार बच्चे आए हैं जिनको छोटे आई है परंतु सभी की स्थितियां अभी सामान्य है सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं उन्होंने बताया कि किसी भी बच्चे को हायर सेंटर रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है जिला अस्पताल में सभी स्कूली छात्राओं का इलाज किया जा रहा है।

बलौदाबाजार में बसपा कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली

बलौदाबाजार। एससी एसटी संगठनों के भारत बंद का बलौदाबाजार जिले में खासा असर दिख रहा है। शहर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दलित समाज के वर्गीकरण पर दिए गए फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दलित समाज के लोगों ने एससी एसटी आरक्षण में उप वर्गीकरण के फैसले को रद्द करने की मांग की है।

बलौदाबाजार में बहुजन समाज पार्टी ने अंबेडकर चौक से गार्डन चौक तक रैली निकाली। एसटी-एससी आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले की वापसी को लेकर बीएसपी कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के बाद बहुजन समाज पार्टी के रायपुर संभाग संयोजक राजकुमार पात्रे ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसटी-एससी वर्ग के उप वर्गीकरण और क्रीमीलेयर को लेकर जो निर्णय दिए हैं। उसके विरोध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज ने आज भारत बंद का आह्वान कर अपना विरोध प्रदर्शन किया है।

राजकुमार पात्रे ने कहा बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के दिशा निर्देश पर प्रदेश भर के सभी जिलों में बीएसपी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। एससी एसटी आरक्षण पर जो निर्णय आया है, उसे केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में प्रस्ताव पारित कर इसे 9वीं अनुसूची में लागू किया जाए। ताकि भविष्य में यह मुद्दा दोबारा न उठे। एससी एसटी में उप वर्गीकरण का फैसला भाई-भाई को लड़ने

वाला काम है, जिसका बहुजन समाज पार्टी विरोध करती है।

एससी एसटी संगठनों के भारत बंद और बीएसपी के प्रदर्शन रैली को ध्यान में रखते हुए बलौदाबाजार पुलिस अलर्ट मोड पर है। शहर के चौक-चौराहों में भारी पुलिस बल तैनात किया है। सुरक्षा की दृष्टि से जिले भर में भी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी को रोका जा सके।

भारत बंद को सफल बनाने सुबह से सड़कों पर दिखे आदिवासी समाज

जगदलपुर। दलित और आदिवासी संगठनों ने बुधवार को %भारत बंद% का आह्वान किया है। यह बंद हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर बुलाया गया है। 'नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन्स' (एनएसीडीएओआर) ने मांगों की एक सूची भी जारी की है। इसमें सबसे अहम अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए न्याय और समानता की मांग हैं।

छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सुबह से ही आदिवासी समाज भारत बंद को सफल बनाने के सड़कों पर दिखाई दिए। इस बंद के दौरान किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना घटित ना हो इसके लिए पुलिस विभाग की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। वहीं, आदिवासी समाज के लोग सुबह से ही हाथ में बोर्ड लेकर सड़कों पर दिखाई दिए।

राष्ट्रीय राजमार्ग में सुबह से ही आदिवासी समाज के लोग दिखाई दिए, जहां रायपुर से आने वाली वाहनों को आसना के पास ही रोक दिया गया। इसके अलावा कुछ वाहनों को नया पुल से पहले रोक दिया गया। वाहनों के इस तरह से रोके जाने से सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई।

बस्तर बंद से एक ओर जहां लोगों को परेशानी हुई, वही इस बंद के दौरान ऑटो चालक के द्वारा सवारियों से मनमाना किराया भी लिया गया। मेडिकल कालेज हॉस्पिटल तक जाने का किराया भी 40 रुपये से अधिक का लिया गया।

मनेंद्रगढ़ में महिलाओं ने नाच गाकर दी सावन को विदाई

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। सावन माह खत्म हो चुका है। इस बीच एमसीबी जिले की महिलाओं ने खास अंदाज में सावन को विदाई दी। महिलाओं ने सावन झूला का आयोजन किया। झूले पर चढ़कर महिलाओं ने गीत गाए। सावन को विदाई देते वक्त महिलाओं ने जमकर झूले का आनंद लिया।

एमसीबी के डोमनहिल में बुधवार को महिलाओं ने सावन को विदा किया। कहा जाता है कि महिलाएं पूरे श्रृंगार के साथ सावन माह सेलिब्रेट करती है। इस पूरे माह भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को इस पवित्र महीने में झूला झुलाया था। एमसीबी की महिलाएं सावन की हरियाली के तरह सज संवरकर हरी चूड़ी, हरी साड़ी पहनकर झूला झूलते नजर आई और सावन को विदा किया।

रचना ने कहा सभी बहनों के साथ हम सावन का त्यौहार मनाने आए हैं। सावन का झूला झूलने आए हैं। अपने पति की लंबी उम्र के लिए हमलोग सावन मनाते हैं और सावन झूला झूलकर सावन को विदाई देते हैं।

गीता ने कहा सालों से सावन माह में एक प्रथा चलती आ रही है कि सावन माह में झूला झूलना चाहिए। इसलिए हम सब महिलाएं यहां झूला झूलने पहुंचे हैं।

इस दौरान महिलाओं ने बताया कि इस माह में भगवान शिव ने माता पार्वती को झूला झुलाया था। सदियों से यह प्रथा चलती आ रही है। सावन के महीने में झूला झूलने से सुख समृद्धि मिलती है। साथ ही पति की लंबी आयु भी होती है। इस दौरान महिलाएं मस्ती में झूमती नजर आई।

बलरामपुर में नौकरी का बंपर मौका महिला बाल विकास में आई भर्ती

बलरामपुर। बलरामपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग ने बंपर भर्ती निकाली है। यहां एकीकृत बाल विकास परियोजना बलरामपुर के तहत 45 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। यह वैकेंसी आंगनबाड़ी सहायिका के पदों के लिए है। कुल 45 पोस्ट पर यह भर्ती निकली है। इसके लिए महिलाएं आवेदन कर सकती है। बलरामपुर में आंगबनाड़ी सहायिकाओं के रूप में काम करने के लिए महिलाओं को यह अच्छा मौका मिला है।

महिला बाल विकास विभाग से जारी जानकारी के मुताबिक 20 अगस्त से 10 सितंबर तक पात्र महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। ऑफिस के समय सुबह 9 बजे से शाम पांच बजे तक बलरामपुर महिला बाल विकास विभाग से आवेदन पत्र खरीदकर जमा किया जा सकता है। उसके बाद फॉर्म जमा करने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

इच्छुक और योग्य महिला उम्मीदवार इन 45 पदों पर भर्ती के लिए परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास बलरामपुर के पते पर डाक से आवेदन से भेज सकते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग बलरामपुर की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि निर्धारित समय में अगर एप्लीकेशन नहीं मिलता है तो उसके बाद किसी भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी ने कहा बलरामपुर में आंगनबाड़ी सहायिका के 45 पद खाली हैं। इसके लिए आवेदन मांगा गया है। 20 अगस्त से 10 सितंबर 2024 तक इच्छुक महिला उम्मीदवार आवेदन कस कती हैं। इसे बलरामपुर महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी के कार्यालय में 10 सितंबर तक जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के बाद यह आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में साय सरकार की तरफ से युवाओं को नौकरी देने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। कॉन्स्टेबल की भर्ती प्रक्रिया को लेकर गृह मंत्री ने पहले ही कहा है कि यह चल रही है। अब बलरामपुर के महिला बाल विकास विभाग के तहत नौकरी निकाली गई है।

आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 20 मवेशियों की मौत

कोरबा। कोरबा में वनांचल ग्राम केराकछार में उस समय सनसनी फैल गई, जब आकाशीय बिजली की चपेट में आने से करीब 20 मवेशियों की मौत हो गई। घटना स्थल से थोड़ी दूर होने के कारण चरवाहे बच निकले। घटना में करीब एक दर्जन किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस में मौके का निरीक्षण किया। पोस्टमार्टम के लिए पशुचिकित्सा विभाग को पत्राचार किया है। कोरबा विकासखंड से करीब 20 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत केराकछार स्थित है, जहां रहने वाले अधिकांश ग्रामीण खेती किसानी का काम करते हैं।

ग्रामीणों ने घरों में गाय और बैल भी पाला हुआ है। बताया जा रहा है कि मवेशियों को खुले में छोड़ देने से खेत में लगी फसल को नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। मवेशी खेत में घुसकर लहलहाती फसल को अपना निवाला बना लेते हैं। जिससे बचने ग्रामीणों ने मवेशियों को चराने दो चरवाहे की व्यवस्था किया है। प्रतिदिन की तरह बुधवार की सुबह भी चरवाहे मवेशियों को लेकर चराने जंगल गए थे। वे 11 बजे दो गांव के करीब एक स्थान पर आराम कर रहे थे। थोड़ी दूर में ही मवेशी भी बैठे थे। इस बीच अचानक मौसम ने करवट ली। तेज गरज के बूंदाबांदी होने लगी। चरवाहे मवेशियों को लेकर बस्ती की ओर ले जाते, इससे पहले ही आकाशीय बिजली गिर गया। जिसकी चपेट में आने से 9 गाय, 7 बैल व 4 बछड़े की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई मवेशी झुलस गए। वहीं चरवाहे थोड़ी दूर होने के कारण सुरक्षित बच निकले। उन्होंने गांव पहुंचकर घटना की जानकारी दी।

ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर देखा तो मवेशियों मृत पड़ी हुई थी। जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। रजगामार पुलिस चौकी प्रभारी मानसिंह ध्रुव अपनी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने मौके का मुआयना करते हुए पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सा विभाग को पत्र लिखा है। बुधवार को पुलिस और राजस्व विभाग की मौजूदगी में वैधानिक कार्रवाई उपरांत मृत मवेशियों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

कराते में छत्तीसगढ़ की बेटियों ने दिलाया गोल्ड

भिलाई। कराते इंडिया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा

इंदौर में आयोजित वेस्ट जोन कराते नेशनल चैंपियनशिप में टीम कांता प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। इंदौर से रायपुर की कराते कोच और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी डोजो पद्मा ब्यौहार ने बताया कि छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों की वेदिका अपराजिता, श्रीजल वर्मा और साक्षी श्रीवास्तव ने जूनियर टीम कांता में सर्वोत्तम प्रदर्शन किया और छत्तीसगढ़ को स्वर्ण पदक दिलवाया। इस टूर्नामेंट में राजस्थान, गुजरात, दमन दीव, महाराष्ट्र, गोआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ ने फाइनल में महाराष्ट्र को 2-1 से हराया।

झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई चार क्लीनिक किए गए सील

बिलासपुर। प्रदेश के न्यायधानी में झोलाछाप

डॉक्टरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में कोटा क्षेत्र के करगीखुर्द, शिवतराई, आमने और लमेर में अवैध क्लीनिकों पर छापेमारी की गई, जिसके परिणामस्वरूप चार क्लीनिकों को सील कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जिले में झोलाछाप डॉक्टरों के इलाज के चलते अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए कई क्लीनिकों पर कार्रवाई की है, लेकिन जिले में अभी भी 115 झोलाछाप डॉक्टर सक्रिय हैं। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण इलाकों में झोलाछाप डॉक्टरों के नामों की सूची जारी कर दी है और लोगों को सलाह दी है कि वे इन डॉक्टरों से इलाज न कराएं। विभाग का उद्देश्य है कि जनता को सुरक्षित और गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं मिल सकें और झोलाछाप डॉक्टरों की गतिविधियों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके।

400 की आबादी में आंगनबाड़ी नहीं, कुपोषित हो रहे बच्चे

भिलाई। भिलाई नगर रेलवे कॉलोनी सेक्टर-

7 रेलवे स्टेशन के पास 400 घर होने के बावजूद यहां पर आंगनबाड़ी नहीं है। यहां बस्ती में 10 वर्ष तक के लगभग 100 से ज्यादा बच्चे हैं जिनके लिए आंगनबाड़ी की व्यवस्था नहीं होने से बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। वहीं गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण शिशु भी कुपोषित है। सरकार द्वारा इतनी सारी योजनाएं होने के बावजूद यहां आंगनबाड़ी नहीं होने से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बीजेपी बूथ अध्यक्ष राजा सोनानी, मीना बघेल और प्रमिला सहित अन्य लोगों ने मांग की है कि बस्ती में आंगनबाड़ी खोली जाए।

हाथी के हमले से एक महिला की मौत, एक बुरी तरह जख्मी

गरियाबंद। जिले के पांडुका रेंज में एक बार फिर दंतैल हाथी का आतंक देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक, दो महिलाएं जंगली मशरूम तोड़ने जंगल गए थे। इस दौरान दंतैल हाथी ने एक महिला को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं एक महिला घायल है। इस घटना में पोंड निवासी बरमत बाई कमार की मौत हुई है। वहीं मंगली बाई हमले से बुरी तरह जख्मी हो गई है, जिसे जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इस घटना के बाद विभाग ने पोंड, कूकदा, नागझर सहित 10 से अधिक गांव में अलर्ट जारी कर किया। बता दें कि दंतैल हाथी चंदा दल से बिछड़ कर बीते एक माह से पंडुका व फिंगेश्वर रेंज इलाके में लगातार घूम रहा है। महिलाओं पर हमला के बाद हाथी उसी स्थल के आसपास मौजूद है, जिसके कारण मृतिका का शव लाने में वन अमला को संघर्ष करना पड़ रहा है। लगातार हो रही घटना के चलते इलाके में दहशत का माहौल भी है।

व्यवसायी के बेटे की गोली मारकर हत्या

सरगुजा। अंबिकापुर से सटे चठिरमा जंगल से एक युवक का शव बरामद किया गया है। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि युवक को तीन गोलियां मारी गई है। युवक की शव मिलने की सूचना पर मौके पर गांधीनगर पुलिस, फोरेंसिक एक्सपर्ट और एडिशनल एसपी पहुंचे हैं। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जिस युवक का शव बरामद किया गया है उसके पिता व्यवसायी हैं। व्यवसायी का पुत्र मंगलवार शाम को घर से निकला था, लेकिन वो घर नही आया। लापता होने की आशंका पर परिजन ने गांधीनगर थाने में सूचना दी। इसके बाद पुलिस युवक के मोबाइल लोकेशन के आधार पर तलाश कर रही थी। लेकिन फोन बंद था। मोबाइल सीडीआर के आधार पर कुछ संदेहियों से पूछताछ करने पर पुलिस ने युवक का लोकेशन मिला। लेकिन उस लोकेशन पर पहुंचने के बाद पुलिस को कार के अंदर युवक का शव मिला। एएसपी अमोलक सिंह ढिल्लो ने कहा गांधीनगर पुलिस ने गुम इंसान कायम करने के बाद मोबाइल लोकेशन निकाला तो मोबाइल बन्द था।

भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पैरी नदी के रेत में किया अभ्यास

कहा- फर्स्ट बीच एशियन कप में वुड बॉल गेम के लिए सटीक स्थान मिला

गरियाबंद। फर्स्ट बीच एशियन कप में वुड बॉल गेम के लिए चयनित भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने गरियाबंद के पैरी नदी के रेत में 5 दिन तक अभ्यास किया। बता दें, कोरिया के डोंगे में 26 अगस्त से एशियन कप प्रतियोगिता शुरू होगी। वुड बॉल गेम के खिलाड़ियों ने कहा कि उन्हें टूर्नामेंट की तैयारी के लिए सटीक स्थान मिला। इसके लिए उन्होंने कलेक्टर का भी आभार जताया।

छत्तीसगढ़ वुड बॉल एसोसियशन के सचिव जितेंद्र पटेल ने बताया कि 26 अगस्त से 1 सितंबर तक कोरिया के डोंगे में फर्स्ट बीच एशियन वुड बॉल गेम का आयोजन हो रहा है। भारतीय वुड बॉल संघ के तत्वाधान में टीम में 9 खिलाड़ी चयनित

हैं। टीम में केरल,मुंबई,एमपी,सीजी के खिलाड़ी चयनित हुए हैं। बीच गेम के प्रेक्टिस के लिए पैरी नदी का लम्बा चौड़ा और साफ रेतीला मैदान काफी उपयुक्त था। छत्तीसगढ़ संघ ने इस स्थान को पहले देखा था। कलेक्टर दीपक अग्रवाल के विशेष सहयोग से 5 दिन का प्रेक्टिस आज संपन्न हुआ है।

टीम के कैंप कोच श्रृंगी शर्मा व ने बताया कि समुद्र तट पर गेम खेला जाना है, यह पहली बार हो रहा है। भिड़-भाड़ से दूर और स्वच्छ इलाका होने के कारण पैरी नदी का रेतीला मैदान हम सभी के अभ्यास के लिए उपयुक्त साबित हुआ। केरल से आई दिया मिलिम बताती हैं कि केरल में बड़े-बड़े समुद्र तट हैं, पर वुड गेम के लायक साफ सुथरा नदी तट गरियाबंद का है।

कलेक्टर भी हैं वुड बॉल के खिलाड़ी

जिले के कलेक्टर दीपक अग्रवाल गोल्फ और वुड बॉल के खेल में माहिर है। इस नाते सीजी वुड बॉल एसोसियशन से भी जुड़े हुए है। इलाके के भौगोलीक परस्थिति से वाकिफ भी हैं। ऐसे में कलेक्टर के पहल पर भारतीय टीम को मैच अभ्यास के लिए बेहतर माहौल मिला, यह जिले के लिए गौरव की बात है कि छालीवुड के बाद अब पैरी का सुंदर नजारा और रेत का मैदान अब किसी राष्ट्रीय खेल के लिए काम आ गया। कलेक्टर अग्रवाल ने इसे भविष्य में स्थाई रूप से अभ्यास स्थान बनाने प्रस्ताव भेजने की बात कही है।

आग का गोला बना ट्रक, एनएच 30 पर हुआ हादसा

केशकाल/जगदलपुर। केशकाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एनएच 30 पर एक चलता ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक जगदलपुर से रायपुर की ओर लोहे की गिट्टी लोड करके जा रहा था। आग ने ट्रक के पिछले पहियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग पर काबू पा लिया गया है। सूचना मिलते ही केशकाल थाना प्रभारी विकास बघेल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कोंडागांव से दमकल वाहन भी बुलाया गया। स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने में मदद की। काफी देर बाद आग पर काबू पा लिया गया।

घटना के कारण एनएच 30 पर यातायात प्रभावित हुआ है। लेकिन राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। पूरी घटना केशकाल थाना क्षेत्र के बहीगांव में घटी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर घायल हुए हैं।

नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए पंजीयन शुरू

महासमुंद। जवाहर नवोदय विद्यालय, सरायपाली में सत्र 2025-26 में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा 2025 के लिए पंजीयन प्रारंभ हो गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय सरायपाली के प्राचार्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस परीक्षा के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2024 है। जिला महासमुंद के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 5 वीं में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं इस परीक्षा के लिए पंजीयन कर सकते हैं। छात्र-छात्राएं लिंक https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs/ के माध्यम से अपना पंजीयन कर सकते है। इस संबंध में अधिक जानकारी और सहायता के लिए, अभ्यर्थी हेल्प डेस्क नंबर +91-8319595289 पर संपर्क कर सकते हैं।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय वामनराव लाखे की पुण्यतिथि पर उन्हें किया नमन

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री वामनराव लाखे की 21 अगस्त को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। श्री साय ने उनके अमूल्य योगदान को याद करते हुए कहा है कि श्री लाखे ने छत्तीसगढ़ में सहकारिता के माध्यम से किसानों सहित लाखों लोगों के आर्थिक विकास की मजबूत आधारशिला रखी। उन्होंने रायपुर में सहकारी बैंक की स्थापना की। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में जन-जागरण के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। खादी के प्रचार-प्रसार के साथ शिक्षा के विकास के लिए भी वे सक्रिय रहे। छत्तीसगढ़ में पहली मासिक पत्रिका के प्रकाशन का श्रेय भी लाखे जी को जाता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि लाखे जी आजीवन सहकारी संगठनों की मजबूती के लिए लगे रहे। उनके प्रयासों का ही परिणाम है कि आज सहकारिता के माध्यम से लाखों लोगों के रोजगार और आगे बढने का सपना सच हो रहा है। सहकारिता के क्षेत्र में श्री लाखे जी का योगदान सदा याद किया जाएगा।

अमित शाह के दौरे को लेकर सीएम हाउस में हाई लेवल मीटिंग

रायपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के आगामी छत्तीसगढ़ दौरे की तैयारी को लेकर बुधवार को रायपुर स्थित सीएम हाउस में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ गृहमंत्री विजय शर्मा और पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री के दौरे से पहले दिए गए निर्देशों की समीक्षा की गई और सुरक्षा तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। बता दें, केंद्रीय गृहमंत्री नक्सल मोर्चे को लेकर सात राज्यों के जीडीपी और मुख्य सचिव की बैठक लेंगे। उनके आगमन से पहले आज बैठक में पुलिस के आला अधिकारी सीएम के समक्ष सुरक्षा व्यवस्थाओं और नक्सल मोर्चे पर किए गए उपायों का प्रजेंटेशन दे रहे हैं। बैठक में नक्सल मामलों समेत प्रदेश के विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें केंद्रीय गृहमंत्री के दौरे को लेकर आवश्यक तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है।

22 अगस्त को होने वाला जनदर्शन स्थगित

रायपर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का हर सप्ताह गुरुवार को होने वाला जनदर्शन इस गुरुवार 22 अगस्त को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है।

तेलीबांधा गोलीकांड का मुख्य आरोपी पंजाब से गिरफ्तार

रायपुर। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा इलाके में हुए गोलीकांड में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस घटना के मुख्य शूटर सागर (25) को पंजाब के बठिंडा से गिरफ्तार कर लिया गया है। सागर का साथी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 10 आरोपितों को पंजाब और झारखंड से गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने अमन साहू गैंग के सदस्य अमनदीप सिंह को भी गिरफ्तार किया था, जो झारखंड के अमन साहू गैंग से जुड़ा हुआ है। जांच में खुलासा हुआ है कि अमनदीप ने शूटरों के लिए बाइक और पैसों की व्यवस्था की थी।

राशन कार्ड बनने के बाद भी नहीं मिला कॉल सेंटर की मदद से हाथ में आया कार्ड

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में अब एक फोन पर समस्या का समाधान मिल रहा है। रायपुर जिले के वार्ड क्रमांक 41 डब्लूआर एस कॉलोनी निवासी श्रीमती तुलसी देवी का सामान्य राशन कार्ड बना था, लेकिन नए राशन कार्ड बनाने के लिए उन्होंने आवेदन किया था. कार्ड बनने के बाद भी नहीं मिल रहा था, तभी उन्होंने जिला प्रशासन के जन समस्या निवारण कॉल सेंटर में फ़ोन किया। जिसके बाद संबंधित विभाग ने प्रकरण की जानकारी दी गई। इसके बाद उन्हें तुरंत नया राशन कार्ड जारी कर दिया। राशन कार्ड मिलने पर श्रीमती तुलसी देवी ने संतुष्टी जताई और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार जताया।

एक पेड़ मां के नाम पर राज्यपाल डेका ने लगाया कचनार का पौधा

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने दुर्ग प्रवास

के दौरान बुधवार को तितुरडीह स्थित कृष्ण कुंज में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कचनार के पौधे का रोपण किया। विधायक श्री गजेन्द्र यादव ने भी जामुन का पौधा लगाया। इस अवसर पर दुर्ग जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में भारत बंद बेअसर, चेंबर ने नहीं किया बंद का समर्थन

रायपुर। अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमीलेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है। भारत बंद को छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन नहीं दिया है। छत्तीसगढ़ में इसका मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। राजधानी रायपुर, बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में भारत बंद का कोई असर देखने को नहीं मिला रहा हैं। साथ ही कई जिलों में व्यापक प्रभाव दिख रहा है।

रायपुर के अंबेडकर चौक में लोग बड़ी संख्या में भारत बंद करवाने निकले हैं। व्यापारियों से बंद को लेकर समर्थन देने कि अपील कर रहें है। एससी-एसटी संयुक्त मोर्चा के लोग झंडा लेकर सड़कों में दिख रहे हैं। इसे लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दूसरी ओर बिलासपुर में जगह-जगह पुलिस के जवान तैनात हैं। यहां स्कूल कॉलेज के साथ दुकानें भी खुली हैं।

समाजवादी पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महासचिव मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। जिसके विरोध में समाजवादी पार्टी छत्तीसगढ़ के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के भाईयों की संवैधानिक अधिकारों को रक्षा के लिए शांतिपूर्ण अंहिसात्मक आन्दोलन एवं भारत बंद को अपना समर्थन देती है। दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ ने भारत बंद का समर्थन किया है। नीला झंडा लेकर प्रदेश के कई जिलों में विरोध कर रहे हैं। राजधानी रायपुर समेत एक-दो जिलों में स्कूल, कॉलेज और अन्य आवश्यक सेवाएं चालू हैं।

कोरबा में एससी एसटी आरक्षक को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के विरोध में बुधवार को बुलाए

गए भारत बंद का कोरबा शहर में कोई खास असर देखने को नहीं मिला। हालांकि दलित समुदाय द्वारा घूम-घूमकर भारत बंद को सफल बनाने को लेकर आह्वान किया जा रहा है। पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक दुजराम बहुजन समाज पार्टी की ओर से समर्थन और बंद के आह्वान पर कोरबा पहुंचे जहां बहुजन समाज पार्टी के सैकड़ो कार्यकर्ता घंटाघर स्थित अंबेडकर जी के मूर्ति पर माली अर्पण कर सभी ने नए कानून नीति का विरोध किया। चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के योगेश जैन ने बताया कि चैंबर ऑफ़ कॉमर्स बैंड का समर्थन नहीं कर रही है लेकिन सम्मान जरूर कर रही है अगर बंद करने आते हैं तो कुछ समय के लिए बंद जरूर किया जा रहा है। इस दौरान शहर में कोई हिंसक घटना ना घटे इसे लेकर पुलिस सचेत रही। एसपी खुद सड़क पर उतरकर पुलिस जवानों को दिशा निर्देश देते नजर आए। कोरबा में भारत बंद के दौरान विषम परिस्थिति निर्मित ना हो सके इसके लिए पुलिस काफी चौकन्नी नजर आई। एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ था,और सड़क पर उतरकर पुलिस बल को निर्देष देते हुए नजर आए। गौरतलब है,कि एससी एसटी वर्ग के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो फैसला दिया है उसे लेकर इस वर्ग में असंतोष का माहौल निर्मित हो गया है,और इस फैसले के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया गया है। हालांकि इस बंद को कोरबा में कोई खास असर देखने को नहीं मिला। आंदोलन वर्ग लोगों से बंद को सफल बनाने को लेकर आह्वान करते जरुर नजर आए।

जगदलपुर में बुधवार की सुबह से ही आदिवासी समाज सड़कों पर दिखाई देते हुए बंद को सफल बनाने में जुटे दिखाई दिखे, वहीं इस बंद के दौरान किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना घटित ना हो इसके लिए पुलिस विभाग की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, वहीं आदिवासी समाज के लोग सुबह से ही हाथ में बोर्ड लेकर सड़कों पर दिखाई दिए। राजमार्ग में सुबह से ही समाज के लोग दिखाई दिए, जहाँ रायपुर से आने वाली वाहनों को आसना के पास ही रोक दिया गया, इसके अलावा कुछ वाहनों को नया पुल से पहले रोक दिया गया, वाहनों के इस तरह से रोके जाने से सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई। बस्तर बंद से एक ओर जहां लोगों को परेशानी हुई, वहीं इस बंद के दौरान ऑटो चालक के द्वारा सवारियों से मनमाना किराया भी लिया गया, मेडिकल कालेज हॉस्पिटल तक जाने का किराया भी 40 रुपये से अधिक का लिया गया।

कबीरधाम जिले में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला है। शहर में व्यापारियों का भी समर्थन मिला, जिससे जिले में दुकान, बाजार बंद रहे। कवर्धा में आज दोपहर दो बजे आमसभा होगी। इसके बाद रैली निकाल कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। रायगढ़ जिले में अभी तक बंद का कोई असर देखने को नही मिल रहा, आम दिनों की भांति यहां का माहौल है।

धमतरी में आदिवासी समाज के लोगों ने दुकानों पर जा-जाकर बंद करवा रहे हैं। इस बीच समाज के लोगों द्वारा दुकान, बाजार बंद करवाने निकले हैं। धमतरी में इसका असर मिलाजुला देखने को मिला। आदिवासी समाज के लोगों ने पूरे जोर लगाकर बंद करवाने निकले, लेकिन व्यापारियों ने इसका समर्थन नहीं किया। लिहाजा धमतरी में आदिवासी समाज के द्वारा बंद का आव्हान किया गया था। जिसका असर मिलाजुला देखने मिला। कुछ दुकानें बंद नजर आई, जबकि कुछ दुकानें चालू रही । इधर चेंबर आफ कॉमर्स का जिलाध्यक्ष ने आदिवासियों का भारत बंद को समाधान नहीं मानते हुए समर्थन देने से इंकार किया।

बीजापुर जिले में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। यहाँ चारों ब्लाकों में जहां व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। तो वहीं चक्काजाम भी किया गया। बीजापुर से होकर पड़ोसी राज्य तेलंगाना व महाराष्ट्र जाने वाली यात्री बसों के पहिये भी थमे रहे। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकाने पूरी तरह से बंद रहे। बीजापुर जिले के भोपालपटनम, भैरमगढ़, बीजापुर व उसूर ब्लाक के मुख्यालय आवापल्ली में खासा असर देखने को मिला। सुबह से ही व्यपारिक प्रतिष्ठाने जहां बंद रहे। तो वही चक्काजाम होने से आवागमन भी प्रभावित रहा। जगदलपुर से बीजापुर की ओर आने जाने वाली यात्री वाहन नहीं चली।

डिप्टी सीएम अरुण साव की बड़ी घोषणा, 900 करोड़ की लागत से

नगरीय निकायों में शहरी अधोसंरचना को किया जाएगा मजबूत : साव

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बुधवार को राज्य के सभी नगरीय निकायों के लिए 450 करोड़ रुपए की राशि जारी किये जाने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत अधोसंरचना विकास के लिए जल्द ही 450 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इस प्रकार, कुल 900 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश के नगरीय निकायों को शहरी अधोसंरचना को मजबूत करने और नए विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने यह घोषणा आज पत्रकार वार्ता के दौरान की, इस दौरान उन्होंने जनसमस्या निवारण शिविर में प्राप्त मांगों और उसके निराकरण की स्थिति की जानकारी साझा की।

उप मुख्यमंत्री साव ने बताया कि नागरिकों की समस्याएं दूर करने और उनकी जरुरतों को समझाने के लिए प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में विगत 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया गया था। शहरी नागरिकों को इसका बेहतर प्रतिसाद मिला है। मैंने खुद कई जनसमस्या निवारण शिविरों में पहुंचकर व्यवस्थाएं देखी थीं और नागरिकों से मुलाकात की थी। मैंने सभी नगर निगमों के आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को यथासंभव मौके पर ही निराकृत करने के निर्देश दिए थे।

बता दें कि जनसमस्या निवारण पखवाड़े के दौरान प्रदेश भर में आयोजित शिविरों में करीब एक लाख 30 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 37 प्रतिशत यानि 48 हजार आवेदनों का निराकरण मौके पर ही कर दिया गया है। दूसरे विभागों से संबंधित आवेदनों को संबंधित विभागों को प्रेषित करने के बाद शेष आवेदनों का परीक्षण कर शीघ्र निराकरण की कार्यवाही की जा रही है। लोगों की जरूरतों और मांगों से संबंधित निर्माण कार्य से जुड़े कार्य बारिश की वजह से नहीं हो पाए हैं। बरसात के बाद ये कार्य तेजी से पूर्ण किए जाएंगे। शहरों में आयोजित जनसमस्या निवारण पखवाड़ा की यह बड़ी सफलता होगी।

जनसमस्या निवारण पखवाड़े के दौरान प्राप्त आवेदनों की स्थिति

प्रधानमंत्री आवास योजना : 17,512 आवेदनों में से 1,181 का त्वरित समाधान किया गया। शिविर स्थल पर ही नए आवास की स्वीकृति, त्रुटियों का निराकरण, और अधूरे आवासों को शीघ्र पूरा करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

पेयजल समस्या : 5,573 में से 1,233 आवेदनों का समाधान शिविर में ही किया गया। नए नल कनेक्शन, पाइपलाइन विस्तार और लीकेज की मरम्मत का कार्य किया गया।

कचरा संग्रहण और साफ-सफाई : 1,796 कचरा संग्रहण से संबंधित आवेदनों में से 1,127 को मौके पर निपटाया गया।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन : 2,263 आवेदनों में से 570 का त्वरित निराकरण किया गया।

सड़क और नाली मरम्मत : 17,655 में से 809 आवेदनों को तत्काल स्वीकृत कर मरम्मत कार्य किए गए। शेष मांगों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

संपत्ति कर और भवन निर्माण : 642 संपत्ति कर से संबंधित आवेदनों में से 380 का समाधान मौके पर किया गया। संपत्ति के नामांतरण और भवन निर्माण की स्वीकृति से संबंधित 1,117 आवेदनों में से 58 का त्वरित निराकरण किया गया।

राशन कार्ड और स्वास्थ्य सेवाएं : 21,701 राशन कार्ड से संबंधित आवेदनों में से 11,541 का समाधान किया गया। 9,701 लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण और 7,613 आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए।

भूमि विवाद और राजस्व प्रकरण : 14,080 आवेदनों में से 3,000 का निराकरण किया गया। बिजली, स्ट्रीट लाइट, मवेशी, आवारा कुत्तों, अतिक्रमण और अवैध निर्माण से संबंधित 30,489 आवेदनों में से 11,146 का समाधान किया गया। शेष आवेदन अन्य विभागों से संबंधित होने के कारण संबंधित विभागों को निराकरण के लिए प्रेषित किए गए हैं।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की सक्रियता की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के विकास और नागरिकों को अधिक सुविधाएं देने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार ने शुरुआती 8 महीनों में नगरीय निकायों को 1250 करोड़ रुपए दिए हैं। इस राशि का उपयोग नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अधोसंरचना विकास और जनसुविधाओं के सुधार के लिए किया जा रहा है।

इसके अलावा, पिछले 8 महीनों में जारी की गई राशि के साथ-साथ नगरीय निकायों को जल्द मिलने वाली 900 करोड़ रुपए को मिलाकर कुल 2150 करोड़ रुपए शहरों के विकास के लिए प्रदान किए जाएंगे। अरुण साव ने जोर देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास राशि की कमी नहीं है और सभी नगरीय निकायों की मांगों और जरूरतों के अनुसार राशि स्वीकृत की जा रही है।

महंत कालेज में मनाया गया सद्भावना दिवस

रायपुर। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर महंत लक्ष्मी नारायण दास महाविद्यालय में सद्भावना दिवस मनाया गया।

सद्भावनादिवस का आयोजन राजीव गांधी स्टडी सर्किल महंत कॉलेज के एनएसएस इकाई द्वारा संयोजक डॉक्टर मुखर्जी एवं लक्ष्मी साहू के नेतृत्व में किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व कुलपति डॉक्टर निगम शंकराचार्य विश्वविद्यालय उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी भारत के स्वप्न द्रष्टा एवं आधुनिक भारत के निर्माता थे उन्हेंने राजीव गांधी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ग्रामीण भारत में जनता की भागीदारी कैसे हो? इसके लिए सुनियोजित ढंग से प्लानिंग करके उसने ग्राम पंचायत की योजना बनाई और कहां की राजीव गांधी के योगदान को भूलाया नहीं जा सकता। दूसरी ओर कॉलेज के प्राचार्य ने राजीव गांधी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राजीव गांधी सच्चे रूप से जो आज आधुनिक भारत दिख रही है उसके निर्माता है। कार्यक्रम में प्रबंध समिति के अध्यक्ष अजय तिवारी ने सभी अथितियों का परिचय कराया एवं राजीव गांधी के द्वार 18 वर्ष के उम्र में वोटिंग का अधिकार दिलवाने की एक बड़ी उपलब्धि से सबको अवगत कराया। कार्यक्रम में प्रो अंजनी शुक्ल, पूर्व अध्यक्ष निजी विश्वविद्यालय, सचिव अनिल तिवारी, सहित सभी प्रध्यापकगण सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रीतम दास ने किया।

गायों की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु कार्य प्रणाली संतों व गौशाला समितियां को विश्वास में लेकर बनाएं सरकार

रायपुर। संत श्री राम बालक दास महात्यागी छत्तीसगढ़ राज्य गो सेवा आयोग के संरक्षक बुधवार को दो दिन के प्रवास पर दिल्ली पहुंचे। संत श्री राम बालक दास ने जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के चातुर्मास कार्यक्रम में सम्मिलित होकर विशेष चर्चा की। सफदरगंज दिल्ली में आयोजित गौ सेवक सम्मान कार्यक्रम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ राज्यों की तरह गायों की स्थिति ठीक नहीं है। सड़कों पर गायों की मृत्यु दर बहुत बढ़ चुकी है एवं गौशाला संचालक समितियां अनुदान की कमी के कारण संकट में है। ऐसे समय पर छत्तीसगढ़ शासन को एक व्यापक गौ सेवा आयोग का गठन करना चाहिए जिसमें छत्तीसगढ़ के गौसेवी संतों एवं गौशाला समिति संचालकों के विचारों को भी शामिल करना चाहिए। संत श्री राम बालक दास जी ने कहा कि 1997 से वे लगातार छत्तीसगढ़ में गौ रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं जब केवल 20 गौशालाएं छत्तीसगढ़ में होती थी 15 वर्षों में 20 गौशाला से लगभग 150 गौशाला का निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन को 9 महीने हो चुके हैं इसके पश्चात भी अभी तक गायों के सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया इसके लिए उन्होंने चिंता व्यक्त की और दूरभाष पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से चर्चा करके कहा कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में गो अभ्यारण्य एवं गौ सेवा आयोग को प्रारंभ किया जाए।

छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, अफसरों का बदली जिम्मेदारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के चार अफसरों का ट्रांसफर किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिकारियों के ट्रांसफर का आदेश जारी हुआ है। इस आदेश में कुल चार आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। इसमें अभिजीत सिंह, प्रभात मलिक, प्रखर चंद्राकर और नम्रता चौबे को सरकार की ओर से नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार के जारी आदेश में 2012 बैच के आईएएस अफसर अभिजीत सिंह, 2015 बैच के आईएएस अधिकारी प्रभात मलिक, 2022 बैच के प्रोबेशनरी अधिकारी प्रखर चंद्राकर और बलौदाबाजार की सहायक कलेक्टर नम्रता चौबे को इधर से उधर किया गया है। इन सभी अधिकारियों की वर्तमान पदस्थापना में परिवर्तन किया गया है।

ये अफसर छत्तीसगढ़ में नए रोल में नजर आने वाले हैं।

2012 बैच के आईएएस अफसर अभिजीत सिंह को हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट का संयुक्त सचिव का एडिशनल चार्ज मिला है। वर्तमान में अभिजीत सिंह गृह और जेल विभाग में संयुक्त सचिव है। 2015 बैच के आईएएस अधिकारी प्रभात मलिक को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग यानी चिप्स के संयुक्त सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है। वर्तमान में प्रभात मलिक चिप्स (छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी) के सीईओ हैं।

इसी तरह 2022 बैच के दो आईएएस प्रोबेशनरी अधिकारी को भी पोस्टिंग मिली हैं। कांकेर के सहायक कलेक्टर प्रखर चंद्राकर को सारंगढ़ का एसडीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है ।वहीं बलौदा बाजार की सहायक कलेक्टर नम्रता चौबे को महासमुंद जिले के सरायपाली का एसडीएम बनाया गया है।

महादेव आनलाइन सट्टा एप मामले की जांच करेगी सीबीआई

■ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिए संकेत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए बिरनपुर हिंसा और सीजीपीएससी घोटाले की जांच के बाद अब महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले की जांच भी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपे जाने की तैयारी है। राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस बात के संकेत दिए हैं कि महादेव सट्टा एप घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में इस घोटाले से जुड़े सभी 70 प्रकरण सीबीआई को सौंपे जाएंगे, जिससे 15 हजार करोड़ रुपये के इस घोटाले में शामिल लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में प्रदेश के कई बड़े नेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों के नाम सामने आए हैं, जिन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी), 420, आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1998 के तहत आरोप दर्ज हैं।

महादेव सट्टा एप घोटाले की जांच सबसे पहले अक्टूबर 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुरू की थी। शुरुआत में दुर्ग, रायपुर, और बिलासपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिनके आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। अगस्त 2023 में ईडी ने पहली गिरफ्तारी की, और इसके बाद यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ दिया गया। अक्टूबर 2023

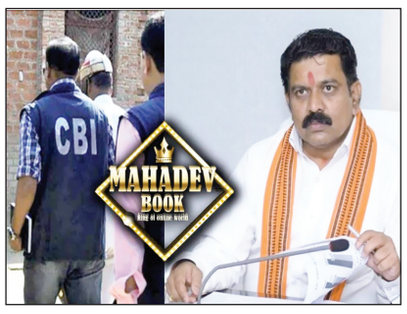

में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी सहयोगियों से पूछताछ भी की, जिनमें उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, ओएसडी मनीष बंछोर और आशीष वर्मा शामिल थे।

महादेव सट्टा एप के प्रमोटरों पर आरोप है कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। नवंबर 2023 में ईडी ने अपनी चार्जशीट में बघेल का नाम भी शामिल किया था। विधानसभा चुनाव से पहले इस मामले को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा था। वर्तमान में साय सरकार के अधीन ईओडब्ल्यू इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब इसे सीबीआई को सौंपने की तैयारी है।

बता दें कि महादेव ऑनलाइन सट्टा एप एक अवैध प्लेटफार्म है, जो सट्टेबाजों को लाइव गेम्स और वर्चुअल खेलों पर दांव लगाने की सुविधा प्रदान करता है। इस एप के जरिए लोग पोकर, तीन पत्ती, ड्रैगन टाइगर जैसे कार्ड गेम्स के साथ-साथ क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस और फुटबॉल जैसे खेलों में भी सट्टा लगाते हैं। एप में वर्चुअल क्रिकेट और अन्य एप्स का उपयोग कर सट्टेबाजी की जाती है, जिससे यह अवैध गतिविधियों का केंद्र बन गया है। अब तक राजधानी रायपुर से जनवरी 2024 से लेकर अब तक 80 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि पूरे प्रदेश में यह संख्या करीब 600 है।

महादेव ऑनलाइन सट्टा एप के दो प्रमुख डायरेक्टर, रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर, अभी भी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है, जिससे जांच को और अधिक सख्ती से आगे बढ़ाया जा सके।

आरक्षण का वर्गीकरण समय की मांग

केसी त्यागी

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में आरक्षण वर्गीकरण की बहस, जो लंबे समय से चली आ रही थी, को सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय से दूर कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत के फैसले में कहा कि राज्यों को राष्ट्रपति ने सूची में अधिसूचित अनुसूचित व अनुसूचित जनजातियों को उपवर्गीकृत करने की अनुमति प्रदान कर दी है, ताकि उन्हें सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में 'अधिक' अधिमान्यता प्रदान की जा सके। यह निर्णय कई मायनों में क्रांतिकारी साबित होगा, क्योंकि देश में वंचित तबकों के अंदर कई तरह के सामाजिक समुदाय जैसे, कामगार, हुनरमंद, कारीगर और बागवानी आदि करने वाले वर्ग सामाजिक न्याय की नीतियों और राजनीति को दुरुस्त करने के लिए लंबे समय से मुखर हैं, लेकिन उन समुदायों की समाज व राजनीति में अदृश्यता है। इसलिए देश की संसद तक उनकी आवाज नहीं आ पाती है। इससे उन आवाजों को भी बल मिलेगा और उन पर विचार किया जा सकेगा। वर्ष 2004 में सुप्रीम कोर्ट की ईवी चिनैया की पांच सदस्यीय पीठ ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत वर्गीकरण पर रोक लगा दी थी, जबकि इस निर्णय में मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'अनुच्छेद 341(2) एक एकीकृत समरूप वर्ग नहीं बनाता है। ऐतिहासिक और अनुभवजन्य साक्ष्य दर्शाते हैं कि अनुसूचित जातियां सामाजिक रूप से विषम वर्ग हैं। इस प्रकार, अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य अनुसूचित जातियों को और वर्गीकृत कर सकता है।' मुख्य न्यायाधीश ने उपवर्गीकरण का विरोध करने वाले अनुसूचित समुदायों के विषय पर कहा कि उनका 'रवैया' ट्रेन के सामान्य डिब्बे में बैठे व्यक्ति जैसा है। सबसे पहले, डिब्बे के बाहर के लोग अंदर?जाने के लिए संघर्ष करते हैं। एक बार वे अंदर पहुंच जाते हैं, तो बाहर के लोगों को उसमें प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। आरक्षण वर्गीकरण के विरोध में कई तरह के भ्रामक तर्कों से वर्गीकरण की बहस को भटकाया जा रहा है, जबकि हमें फैसले को इस तरह से भी देखने की जरूरत है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जाति पदानुक्रम के सबसे निचले पायदान पर स्थित सबसे कम सुविधा प्राप्त समुदायों की चिंताओं को सामने लाकर न्याय की खोज को और गहरा कर दिया है। विरोधी रुख उनके ही वर्ग के अति वंचित वर्गों में उनके लिए अविश्वसनीयता पैदा कर रहा है, जबकि विरोधी रुख अपनाने वालों को सोचना चाहिए कि इससे उनकी असांविधानिक व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती मिलेगी, क्योंकि उनके साथ वे लोग भी खड़े मिलेंगे, जो अब तक उनकी मुहिम में साथ खड़े नहीं दिखाई देते थे, उसका प्रमुख कारण था कि वे मुख्य व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं बन पाए थे। अलग-अलग राज्यों में अनुसूचित जाति की जातियां सामाजिक-राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय हैं। जैसे महाराष्ट्र में तीन दर्जन से अधिक जातियां शामिल हैं, लेकिन महार और मातंग सबसे प्रमुख हैं। इनकी साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से उच्च है। वहीं अनुसूचित जनजाति में गोंड और भील, दो सबसे बड़ी जनजातियां हैं, जबकि राजस्थान की राज्य सूची में कुल 59 अनुसूचित जातियां शामिल हैं, लेकिन मेघवाल सबसे बड़ा अनुसूचित जाति समुदाय है, जिसकी सामाजिक-राजनीतिक स्थिति अन्य के मुकाबले बेहतर है। वहीं अनुसूचित जनजाति में मीणा सबसे प्रमुख जनजाति है, दर्जनों विधानसभा सीटों पर चुनावी नतीजों को प्रभावित करती है। समुदाय की देश भर में पुलिस और नौकरशाही में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। उत्तर प्रदेश और बिहार में जाटव, पासी और दुसाध सबसे प्रमुख और सामाजिक-राजनीतिक रूप से सक्रिय जातियां हैं, जबकि इन्हीं राज्यों में मुसहर, सपेरा, बहेलिया, कलाबाज, वाल्मीकि और बदवाल आदि दर्जनों जातियां बेहद कमजोर स्थिति में हैं। न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा, 'लाभार्थी समूहों के भीतर असमानताओं की जमीनी हकीकत इतनी स्पष्ट है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि एक नौकरशाह और एक शारीरिक मजदूर के बच्चे के साथ एक जैसा व्यवहार करना, भले ही दोनों अनुसूचित जाति समुदाय से हों, सांविधानिक जनादेश को पराजित करेगा।' सामाजिक न्याय और आरक्षण का वर्गीकरण ऐसा मुद्दा है, जिसमें लगातार संशोधन नहीं हुआ, तो यह एक नया जातिवाद गढ़ देगा। अत: वर्तमान में चली आ रही आरक्षण प्रणाली को एंपिरिकल डाटा के आधार पर आरक्षण को दो से अधिक वर्गों में विभाजित किया जाना चाहिए और प्रत्येक उपसमूह के लिए जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी के आधार पर अलग-अलग कोटा निर्धारित किया जाना चाहिए।

नकारात्मक राजनीति है लेटरल एंट्री का विरोध

ललित गर्ग

भारतीय नौकरशाही संरचना के प्रभावी एवं परिणामकारी प्रदर्शन को निश्चित रूप से लेटरल एंट्री प्रक्रिया के साथ पूरक किया जा सकता है। लेटरल एंट्री नई बाहरी प्रतिभाओं को लाकर, सरकारी अधिकारियों को सार्वजनिक कल्याण के लिए और अधिक काम एवं प्रभावी काम करने के लिए प्रेरित करके नियमित सरकारी अधिकारियों को पूरक कर सकते हैं, लेकिन लेटरल एंट्री की प्रणाली को अधिक समावेशी, पारदर्शी और असरदार बनाने के लिए एक निश्चित नीति के साथ आगे बढ़ने एवं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सकारात्मक रवैया अपनाना देश विकास के लिये जरूरी प्रतीत होता है। इसके लिये वर्तमान नरेन्द्र मोदी सरकार ने जो कदम उठाया है, उस पर राजनीति करने करने की बजाय उसमें देशहित को सामने रखा जाना चाहिए। वैश्वीकरण ने शासन के काम को अत्यंत जटिल बना दिया है और यही वजह है कि इस क्षेत्र में विशेषज्ञता और कौशल की मांग पहले से बहुत अधिक बढ़ गई है। अर्थव्यवस्था और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में थिंक-टैंकों की आवश्यकता के मद्देनजर तथा अन्य ऐसे विभागों में जहाँ विशिष्ट प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता होती है, लेटरल एंट्री से संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की जानी प्रांसगिक एवं उपयोगी कदम है।

संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव की भूमिकाओं के लिए प्रतिभाशाली, कार्यक्षम और दक्ष भारतीय नागरिकों से 45 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करके सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री (सीधी भर्ती) का स्वागतयोग्य एवं सराहनीय प्रयोग कर रहा है। भले ही इस मुद्दे को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों में विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। वैसे भी ऐसे राजनीतिक लोगों एवं दलों की आंखों में किरणें आंज दी जाये तो भी वे यथार्थ को नहीं देख सकते। क्योंकि उन्हें उजाले के नाम से एलर्जी है। विपक्षी दलों विशेषत: कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के आरक्षण की उपेक्षा के लिए सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री नीति की आलोचना की है। जबकि भारत में सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री का तात्पर्य सरकार के मध्य और वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर पेशेवरों एवं प्रतिभाशाली कर्मियों की भर्ती से है। जिसमें प्रतिभाशाली एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य विशिष्ट कौशल और विशेषज्ञता लाना है जो पारंपरिक नौकरशाही ढांचे में उतनी प्रभावी प्रतीत नहीं हो रही है। कई संभावित और अच्छे प्रशासक हैं जो अपनी कम उम्र के दौरान सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग नहीं लेते हैं। लेटरल एंट्री उन्हें शासन तंत्र का हिस्सा बनने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का अवसर प्रदान करता है। नया भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत निर्मित करने में इन प्रतिभाओं का उपयोग होना राष्ट्र में एक नयी रोशनी का अवतरण हो सकता है।

देखा यह गया है कि जब भी ब्यूरोक्रेसी में सुधार की चर्चा होती है, तो इसका विरोध होने लगता है, जो विरोधाभासी एवं विडम्बनापूर्ण होने के साथ-साथ संकीर्ण राजनीति का द्योतक हैं। कांग्रेस और कुछ अन्य दलों की ओर से जिस तरह लेटरल एंट्री पर आपत्ति जताई जा रही है, वह यही बताती है कि नकारात्मक राजनीति की जा रही है। यह आश्चर्जनक है कि ऐसे देश-विकास एवं राष्ट्र-निर्माण के निर्णयों एवं मुद्दों का विरोध करने की राजनीति की कमान राहुल गांधी अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हैं। कम से कम उन्हें तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी को यह नहीं भूलना चाहिए कि वित्त सचिव के रूप में मनमोहन सिंह की नियुक्ति लेटरल एंट्री ही थी और वह भी बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया के। भारत में लेटरल एंट्री कोई नई बात नहीं है। पहले भी भारत में इसका फायदा उठाया जा चुका है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की नियुक्ति लेटरल एंट्री से ही की जाती रही है। पूर्व आर्थिक सलाहकार मोंटेक सिंह अहलूवालिया, आधार की नींव रखने वाले नंदन नीलेकणि जैसी बड़ी हस्तियां इसी के जरिए प्रशासन में शामिल हुईं। यह व्यवस्था तदर्थ आधार पर की गई है, यह संस्थागत नहीं है। लेटरल एंट्री की व्यवस्था सिर्फ भारत में ही है। ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे पश्चिमी देशों में पहले से ही सभी क्षेत्रों के योग्य कर्मियों के लिए विशिष्ट सरकारी पदों को खोल दिया है। यह नौकरी के लिए बेहतरीन प्रतिभाओं को आकर्षित करने का एक बेहतर तरीका पाया गया है।

स्पष्ट है कि कांग्रेस एक बार फिर अपने शासन के समय सुधार की दिशा में उठाए गए कदम का विरोध कर रही है। इसके विपरीत वर्तमान सरकार एक तय प्रक्रिया के तहत लेटरल एंट्री कर रही है। इसी कारण इसकी जिम्मेदारी संघ लोक सेवा आयोग को दी गई है। कांग्रेस एवं विपक्षी दलों को यह भी पता होना चाहिए कि लेटरल एंट्री के जरिये जो नियुक्तियां की जा रही हैं, वे अस्थायी हैं। ये नियुक्तियां केवल तीन वर्ष के लिए हैं और उनमें अधिकतम दो वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। प्रशासन में सुधार की हर पहल को आरक्षण से जोड़ना केवल यही नहीं बताता कि वोट बैंक की सस्ती राजनीति अनियंत्रित हो रही है, बल्कि यह भी इंगित करता है कि आरक्षण को हर मर्ज की दवा मान लिया गया है। यह ठीक नहीं कि होनी को अनहोनी बनाने का प्रयत्न हो।

वैसे लेटरल एंट्री राष्ट्रहित का मुद्दा है। जिस पर 2002 की संविधान समीक्षा आयोग ने भी सिफ़ारिश वकालत की। मनमोहन सिंह के समय 2005 की द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर लेटरल एंट्री के लिए एक संस्थागत और पारदर्शी प्रक्रिया की सिफारिश की। स्पष्ट है कि कांग्रेस एक बार फिर अपने शासन के समय सुधार की दिशा में उठाए गए कदम का विरोध कर रही है। नीति आयोग ने अपने तीन-वर्षीय कार्य एजेंडा में लेटरल एंट्री के विचार का समर्थन किया। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि लेटरल एंट्री से विशेष ज्ञान और प्रशासनिक कौशल को शामिल करके शासन में सुधार की क्षमता को विकसित किया जा सकता है। शासन में सचिवों का क्षेत्रीय समूह ने भी लेटरल एंट्री प्रणाली का समर्थन किया। यह तर्क दिया गया कि लेटरल एंट्री प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले पेशेवरों को पेश करके सार्वजनिक सेवाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाया सकता है और उसे उच्च परिणामकारी बनाया जा सकता है।

विरोध के लिये विरोध करने की सोच एवं उद्देश्यहीन, उच्छृंखल, विध्वंसात्मक नीति के द्वारा किसी का भी हित सधता हो, ऐसा प्रतीत नहीं होती। राहुल गांधी और कुछ अन्य विपक्षी नेताओं की ओर से यह जो माहौल बनाया जा रहा है कि लेटरल एंट्री के जरिये विभिन्न मंत्रालयों में विशेषज्ञों की नियुक्तियों से आरक्षित वर्गों के हितों को नुकसान होगा, उसका इसलिए कोई औचित्य नहीं, क्योंकि यह कहीं नहीं कहा गया है कि इन वर्गों के लोग आवेदन नहीं कर सकते। राहुल गांधी किस तरह अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए एक झूठा विमर्श खड़ा रहे हैं, इसका पता इससे भी चलता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय स्वयं उन्होंने पूर्व सैन्य अधिकारियों को लेटरल एंट्री के जरिये सिविल सेवाओं में शामिल करने का वादा किया था। लेटरल एंट्री का उद्देश्य है कि जहां कहीं भी कुशल और जानकार लोग हों, उनकी प्रशासन के संचालन में सेवाएं ली जाएं, ताकि सरकारी नीतियों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इसमें कोई दो राय नहीं कि ब्यूरोक्रेसी में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले इसे राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने की भी आवश्यकता है।

राजनीतिक रूप से मजबूत और स्थिर नरेंद्र मोदी की सरकार ने कंपनियों के दिवालिया होने से जुड़े विवादों के निपटारे, जीएसटी लागू करने, नोटबंदी और कृषि क्षेत्र जैसे कई अहम सुधार किए हैं। मोदी सरकार ने श्रम कानूनों को भी सरल बनाया है। लेकिन, इन सुधारों को लेकर उन्हें उस वक्त के मुकाबले कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है, जब पहले पहल इन सुधारों का प्रस्ताव रखा गया था। लेटरल एंट्री जैसे मुद्दे पर भारी विरोध के बादल मंडरा सकते हैं, इसके लिये भाजपा और साथ ही मोदी सरकार को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि विपक्षी दल उसके खिलाफ झूठा नरेटिव खड़ा कर जनता को गुमराह न करने पाएं।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

पद्य संख्यान विधि

गतांक से आगे...

हम यहां पद्यसंख्यान विधि का निरूपण कर देना आवश्यक समझते हैं। (1) पद्य या श्लोक सामान्यतया अनुष्टुप् संख्यात्मक 32 अक्षरों के समुदाय को कहते हैं। (2) अध्यायों की पुष्पिकाएं भी संख्या में सम्मिलित हैं परन्तु उनमें अक्षरों की संख्या का नियम लागू नहीं। प्रत्येक का एक पद्य ही माना जाता है, यथा- इति श्री... पुराणे... अमुक... चरित्रवर्णने अध्याय: इत्यादि। (3) वाक्य का पूर्णविराम हो जाने पर श्लोकार्थ को भी एक पद्य गिना जाता है।

(4) वाक्य विराम की सापेक्षता में डेढ़ श्लोक को भी एक पद्य समझा जाता है। (5) बहुत से स्तोत्रों में उपजाति आदि वृत्तों के प्रत्येक श्लोक को एक माना जाता है। वहां दतीस अक्षरों वाला नियम लागू नहीं होता। (6) जिन ग्रन्थों का नियमित पारायण होता है उनके मध्यवर्ती खास खास स्तोत्रों के एक ही श्लोक के अनेक नम: शब्दों के अनुसार उतने ही पद्य मान लिये जाते हैं, यहाँ भी बत्तीस अक्षरों वाला नियम लागू नहीं होता। (7) प्रत्येक... उवाच को एक पद्य माना जाता है।

(8) मुख्य श्रोता वक्ता के सम्वाद से पूर्वापरवर्ती अंश को पारायण- प्रधान पुराणों में परिगणित भी नहीं किया जाता।

उपर्युक्त नियमों की छाया पाठकों को मार्कण्डेय-पुराणान्तर्गत जगत् प्रसिद्ध ग्रन्थ %दुर्गा सप्तशती% की प्रत्येक प्रति में उपलब्ध हो सकती है। अत: यहाँ उदाहरण देना व्यर्थ है। तथापि किस पुराण में किन किन नियमों के अनुसार पद्य, पद्यांश, तथा बह्वक्षर वृत्तों की गणना होनी चाहिये, और उसके कौन 2 स्तोत्र उपर्युक्त नियमों में आबद्ध हो सकते हैं - यह विवेचन गुरु-शिष्य परम्परागत-सम्प्रदाय पर निर्भर है।

क्रमश: ...

हरिशंकर परसाई

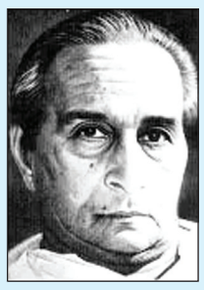

हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त, 1924 को मध्यप्रदेश के जमानी में हुआ। वह देश के जानेमाने व्यंग्यकार थे। राजनीतिक विषयों पर उनकी अद्भुत पकड़ थी। किसी भी प्रकार की नौकरी का मोह छोड़कर परसाई ने स्वतंत्र लेखन को ही जीवनचर्या के रूप में चुना। जबलपुर से वसुधा नाम की साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली। घाटे के बावजूद कई वर्षों तक उसे चलाया, अंत में परिस्थितियों ने बंद करने के लिए विवश कर दिया। अनेक पत्र-पत्रिकाओं में वर्षों तक नियमित स्तंभ लिखे। इनके अतिरिक्त परसाई ने कहानियाँ, उपन्यास एवं निबंध भी लिखे।

उनकी कृतियों में उपन्यास- रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल; कहानी-संग्रह- हँसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे; व्यंग्य निबंध संग्रह- तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, वैष्णव की फिसलन, 'पगडण्डियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, प्रेमचंद के फटे जूते, आवारा भीड़ के खतरे, सदाचार का ताबीज, अपनी अपनी बीमारी, दो नाक वाले लोग, काग भगोड़ा, माटी कहे कुम्हार से, ऐसा भी सोचा जाता है, विकलांग श्रद्धा का दौर, तिरछी रेखाएँ और संस्मरणात्मक निबंध- हम एक उम्र से वाकिफ हैं, जाने पहचाने लोग शामिल है।

हरिशंकर परसाई के लेखन की यह विशेषता है कि वे केवल विनोद या परिहास के लिए नहीं लिखते। उनका सारा लेखन सोद्देश्य है और सभी रचनाओं के पीछे एक साफ-सुलझी हुई वैज्ञानिक जीवन-दृष्टि है, जो समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार, ढोंग, अवसरवादिता, अन्धविश्वास, साम्प्रदायिकता आदि कुप्रवृत्तियों पर तेज रोशनी डालने के लिए हर समय सतर्क रहती है। उनके कहने का ढंग चाहे जितना हल्का-फुल्का हो, किन्तु हर निबंध आज की जटिल परिस्थितियों को समझने के लिए एक अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है।

पगडंडियों का ज़माना पुस्तक में हिंदी के सबसे सशक्त और लोकप्रिय व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई के लगभग दो दर्जन निबंध संगृहीत हैं। प्राय: सभी निबंध 'नई कहानियाँ', 'धर्मयुग', 'ज्ञानोदय' आदि प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। शीर्षक निबंध, जिसके आधार पर पूरी पुस्तक का नामकरण किया गया है, आज के इस ज्वलन्त सत्य को उद्घाटित करता है कि सभी लोग किसी-न-किसी तरह 'शॉर्टकट' के चक्कर में हैं। इस तरह इस पुस्तक का हर निबंध आज की वास्तविकता के किसी-न-किसी पक्ष पर चुटीला व्यंग्य करता है।

हरिशंकर परसाई देश में सियासत पर व्यंग्य के जागरुक प्रहरी रहे हैं। ऐसे प्रहरी जो खाने और सोने वाले तृप्त आदमियों की जमात में हमेशा जागते और रोते रहे। उनकी रचनाओं में जो व्यंग्य है, उसका उत्प्रेरक तत्व यही रोना है। रोनेवाले हमारे बीच बहुत हैं। कहते हैं रोने से ही जी हल्का होता है। वे जी हल्का करते हैं और फिर रोते हैं। झरना बन जाता है उनका मानस। उनकी शोकमग्नता आत्मघाती भी होती है। जनभाषा के कवि हैं कबीर, जिन्होंने राह के बटमारों की गतिविधियों को खूब पहचाना।

यूक्रेन-रूस की जंग खत्म कराएगा भारत?

राजेश बादल

ढाई साल से अधिक समय से जारी रूस और यूक्रेन की जंग क्या निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है? यह सवाल भारत में और समंदर पार बैठे कूटनयिकों के जेहन में चल रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री अब 23 अगस्त को यूक्रेन जा रहे है। उनकी यात्रा के बारे में अधिकृत तौर पर बताया गया है कि जंग समाप्त करने की दिशा में बात हो सकती है। बीते सप्ताह यूक्रेन ने रूस पर बड़ा आक्रमण करके चौंकाया था।

निश्चित रूप से रूस इतने बड़े आक्रमण के लिए तैयार नहीं था और इस हमले ने उस पर दबाव बनाया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के एक हजार किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। 82 से अधिक गांव और कुछ शहर उसके अधिकार में आ गए हैं। यूक्रेन का यह भी कहना है कि उसने तीन दिनों में दो बड़े पुल ध्वस्त कर दिए हैं। इन पुलों के माध्यम से रूसी सेना को साजो-सामान की आपूर्ति होती थी। इससे पहले कि जंग किसी भयानक मोड़ पर पहुंचे और दोनों देशों के लिए कोई अप्रिय स्थिति बने, अब वे बातचीत की टेबल पर आने के लिए तैयार हो सकते हैं। ऐसे संकेत हालिया दौर के घटनाक्रम दे रहे हैं।

बीते दिनों जब भारत के प्रधानमंत्री रूस गए थे तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपनी नाखुशी जताई थी। जिस तरह से प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति से गले मिले और वहां का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया, उससे यूक्रेन खफा था और उसने अप्रसन्नता का इजहार किया था। उसे ऐसा करने का अधिकार है लेकिन पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को अतीत के अध्याय अवश्य पलट लेने चाहिए। क्या जेलेंस्की को याद है कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो भारत पहला देश था, जिसने यूक्रेन को मान्यता दी थी और एशिया में पहला यूक्रेनी दूतावास भी भारत में ही खुला था। पर, यूक्रेन भारत की इस सदाशयता को भूल गया और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए अनिवार्य दूसरा परमाणु परीक्षण किया तो वह संयुक्त राष्ट्र में भारत पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन कर रहे देशों के साथ जाकर खड़ा हो गया।

इसके बाद उसने लगातार भारत को नाराज करने वाले कदम उठाए। उसने पाकिस्तान को टैंकों के इंजन बेचे, सैनिक साजोसामान और हथियारों की सप्लाई लगातार जारी रखी। भारत के विरोध पर भी उसने ध्यान नहीं दिया। आज भी उसकी नीति कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का साथ देने की है। ऐसी स्थिति में भारत से वह किस आधार पर समर्थन की उम्मीद कर सकता है? क्या

यूक्रेन को नहीं सोचना चाहिए कि चीन और पाकिस्तान से शत्रुतापूर्ण रिश्तों के होते हुए भारत रूस को भी कैसे नाराज कर सकता है? यूक्रेन और भारत के बीच सिर्फ तीन-साढ़े तीन अरब डॉलर का कारोबार क्या दुर्बल संबंधों का सबूत नहीं है? इसके बावजूद भारत ने यूक्रेन को जंग के दरम्यान बड़ी संख्या में राहत सामग्री भेजी है। दूसरी ओर पाकिस्तान और यूक्रेन के बीच कारोबार का आंकड़ा इससे अधिक है।

फिर भी एक बार हम इन समीकरणों को भूलकर मौजूदा हालात को देखें तो पाते हैं कि यूक्रेन और रूस अब जंग से ऊब चुके हैं। रूस जंग में जिस कामयाबी की उम्मीद कर रहा था, वह उसे नहीं मिली है। उधर यूक्रेन यूरोपीय देशों से जिस बड़े फौजी समर्थन की आशा कर रहा था, वह उसे हासिल नहीं हुआ है। पंद्रह साल से यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाने की अर्जी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है।

दोनों देशों की सेनाएं अब थकने लगी हैं। बीते दिनों जब भारतीय प्रधानमंत्री रूस गए थे तो उन्होंने साफ कहा था कि जंग से शांति का रास्ता नहीं निकलता। शांति के लिए बातचीत का मार्ग ही श्रेष्ठ होता है। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत जो प्रयास कर रहा है, उसके लिए वे आभारी हैं। पुतिन के इन शब्दों का अर्थ निकाला जाए तो कहा जा सकता है कि जंग जितनी लंबी चलेगी, रूस की मुश्किलें बढ़ेंगी।

इसलिए रूस के पास परदे के पीछे कूटनीतिक चर्चाओं के लिए भारत से उपयुक्त कोई दूसरा देश नहीं है। यह काम वह चीन को नहीं सौंप सकता, क्योंकि यूक्रेन को समर्थन दे रहा अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी चीन को मध्यस्थ के तौर पर कभी स्वीकार नहीं करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी अपने बयान में कहा है कि भारत की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। कूटनीति और बातचीत से ही संघर्ष समाप्त हो सकता है। स्थाई शांति स्थापित हो सकती है।

भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन से पहले पोलैंड जाएंगे. पोलैंड इस जंग में यूक्रेन का सबसे प्रबल समर्थक है। लेकिन अब इस जंग का असर उसकी आंतरिक सेहत पर भी पड़ रहा है इसलिए उसे भी बैकडोर बातचीत के लिए तैयार होना चाहिए। भारत का कोई प्रधानमंत्री 45 साल बाद पोलैंड जाएगा। इसी तरह यूक्रेन के जन्म से भारत के किसी प्रधानमंत्री ने यूक्रेन यात्रा नहीं की है। यदि इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री यूक्रेन जा रहा है तो उसके संदेश को समझने की जरूरत है। यह तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जब भारत पर रूस का साथ देने के आरोप लग रहे हैं।

पोलैंड के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। जब यह जंग शुरू हुई थी तो चार हजार भारतीय छात्रों को यूक्रेन से निकालने में पोलैंड ने भारत की सहायता की थी। भारत की परदे के पीछे की इस ऐतिहासिक पहल को और कुछ नाटो देशों का समर्थन मिल सकता है। अमेरिका के बारे में कुछ कहना फिलहाल अनिश्चित है। नाटो में शामिल कई देश रूस से अपने संबंध नहीं बिगाड़ना चाहेंगे। उम्मीद करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से रूस और यूक्रेन बातचीत की मेज पर साथ आ जाएंगे।

आज का इतिहास

1707 स्वीडन और प्रशिया ने सैन्य संधि पर हस्ताक्षर किया।
1711 रानी ऐनी के युद्ध-ए ब्रिटिश ने क्यूबेक पर हमला करने का प्रयास किया, जिसमें सेंट लॉरेंस नदी पर आठ जहाज बर्बाद हो गए।
1717 स्पेनिश सैनिकों ने सर्दीनिया पर उतारा गया।
1762 एन. फ्रेंकलिन अमेरिकी अखबार न्यूपोर्ट आर आई, मर्करी की पहली महिला संपादक बनी।
1775 किंग जॉर्ज III ने खुले विद्रोह में शामिल होने के लिए कॉलोनियों की घोषणा की।
1791 हाईटियन क्रांति की शुरुआत करते हुए, सेंट-डोमिंग्यू के फ्रांसीसी उपनिवेश में एक गुलाम विद्रोह हुआ।
1795 राष्ट्रीय संविधान द्वारा वर्ष III के संविधान की पुष्टि की गई।
1798 आयरिश विद्रोह की सहायता के लिए फ्रांसीसी सैनिकों काउंटी मायो में किल्कमुमिन में स्थित किया गया।
1817 ब्राजील के अररकारा शहर की खोज हुई।
1848 संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यू मैक्सिको से समझौता किया।
1849 इतिहास में पहली बार हवाई छाप: ऑस्ट्रिया ने वेनिस के इतालवी शहर के खिलाफ पायलटलेस गुब्बारे की शुरुआत की।
1851 ऑस्ट्रेलिया में सोने की खानों के इलाके की खोज हुई।
1851 नौका अमेरिका ने इंग्लैंड के आइल ऑफ वाइट के पास पहली अमेरिका कप रेस (ट्रॉफिप्रिक्टेड) जीती।
1851 यॉट अमेरिका ने इंग्लैंड के तट पर पहला अमेरिकी दौड़ कप जीता।
1864 हेनरी डुनेंट के नेतृत्व में रेड क्रॉस आंदोलन आधिकारिक तौर पर बारह यूरोपीय देशों ने पहले जेनेवा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए, जो रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना कर रहे थे।
1865 विलियम शेपार्ड को तरल साबुन के लिए पहले अमेरिकी पेटेंट जारी किया गया।
1872 ऑस्ट्रेलियाई ओवरलैंड टेलीग्राफ लाइन पूरा किया गया, पहली बार ऑस्ट्रेलिया और बाकी दुनिया के बीच एक टेलीग्राफिक लिंक प्रदान किया गया।

सामाजिक समरसता से बनेगा सशक्त भारत

प्रो. संजय द्विवेदी

समता, ममता और समरसता हमारे भारतीय लोकजीवन का अभिन्न अंग है। हम जिस देश में रहते हैं उसके ऋषि कहते हैं- 'सर्वभूतहिते रताः।' प्रकृति से साथ हमारा संवाद बहुत पुराना है। इसलिए हमने अपनी समूची सृष्टि को स्वीकारा। किसी को विरोधी नहीं माना। पेड़, पहाड़, नदियां, समुद्र, वनस्पतियां, जलचर, नभचर, जीव-जंतु, मनुष्य सबमें ईश्वर का वास मानने वाले हम ही हैं। हम ही कह पाए जो जड़ में है वही चेतन में है। कण-कण में ईश्वर का वास मानने वाली संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है।

काल के प्रवाह में विचलन स्वाभाविक है। आज हमें समता, समरसता और अधिकारों की बात करनी पड़ रही है। सुधारों की बात करनी पड़ रही है, क्योंकि विचलन ने हमें उन मूल्यों से विरत कर दिया, जहां एक आदमी को ईश्वर बन जाने की स्वतंत्रता थी। आदमी का मनुष्य बनना और फिर देवत्व की तरफ बढ़ना साधारण नहीं है। उसके मूल्यनिष्ठ होते जाते की मुनादी है, घोषणा है। ऋषि कहते हैं- 'मर्नु भवः' यानि मनुष्य बनो। यही बाद बाद में गालिब के मुंह से निकलती है-

यूं तो मुश्किल है हर काम का आसां होना
आदमी को मयस्सर नहीं इंसा होना।

यानि जन्म से आप 'आदमी' हो सकते हैं किंतु 'मनुष्य' या 'इंसान' एक प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही आप बनते हैं। हमारे समाज में मनुष्य बनाने के स्कूल थे। हमारा परिवार, समाज और विद्यालय तथा धर्मगुरु इस प्रक्रिया को संभव करते थे। मनुष्य-मनुष्य में भेद को हमने अपराध माना। इसीलिए गुरू घासीदास कहते हैं- मनखे-मनखे एक हैं। इसी बात को गांधी छुआछूत के संदर्भ में कहते हैं- अस्पृश्यता ईश्वर और मानवता के प्रति अपराध है। हिंदू समाज में आई जड़ता को तोड़ने के लिए समय-समय पर सुधारवादी आंदोलन चलते रहे हैं। हिंदु स्वयं एक ऐसा समाज है, जिसने अपने आत्मसुधार के लिए निरंतर यत्न किए हैं। हम सब ऋषियों की संतति हैं यह भाव लेकर काम करते रहे हैं। गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, कबीर, नानक, गुरू गोरखनाथ, गुरू घासीदास, संत रविदास से लेकर एक पूरी परंपरा जड़ताओं और कुरीतियों पर प्रहार करते हुए आत्मालोचन के लिए प्रेरित करती रही है। समय के सच को समझना और अपने समय के कठिन सवालों से जूझना हिंदुत्व की प्रकृति रही है। गुलामी के कालखंड में आई कुछ नकारात्मक वृत्तियों को समाप्त करने के लिए राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, बाबा साहब डा.भीमराव आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पंडित सुंदरलाल शर्मा जैसे अनेक नायक हमारे समाज में समरसता के मंत्रदृष्टा बनकर आते रहे हैं। कोई भी समाज कुरीतियों से मुक्त नहीं है। हर समाज में समय के साथ कुछ गिरावट आती है। मूल बात यह है कि क्या समाज अपनी गिरावट के विरूद्ध तनकर खड़ा होता है या नहीं। उसमें आत्मालोचन और आत्मसमीक्षा की प्रवृत्ति है या नहीं। हिंदु समाज इस अर्थ में खास है कि उसने प्रश्नाकुलता को समाज में मान्यता दी है। वह सती प्रथा, बाल विवाह, छूआछूत, जातीय

विद्वेष के विरूद्ध खड़ा हुआ और स्त्री शिक्षा, स्त्री को न्याय,मनुष्य की बराबरी के मानकों को स्वीकार करते हुए एक नया भारत बनाने की ओर है। समाज में 'जातिद्वेष' मान्यता नहीं है।

हम मानते रहे हैं कि जाति का गौरव होना चाहिए किंतु जाति भेद ठीक नहीं। हमारे अनेक ऋषि व्यास, बाल्मीकि, संत रविदास, संत रसखान हमारे श्रद्धास्थान हैं। क्योंकि हमें बताया गया और हमने माना भी कि जाति-पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हमारी परंपरा के सर्वोच्च नायक भगवान श्रीराम के समरसता इन्हीं गुणों से मर्यादा पुरूषोत्तम बने। अपनी उदार भावनाओं से वे 'शबरी के राम' हैं तो 'बाल्मीकि के भी राम' हैं। वे तुलसी के राम हैं तो कबीर के भी राम हैं। वे हनुमान के हृदय में हैं तो आहिल्या के भी उद्धारकर्ता हैं। वे निषादराज के परममित्र हैं, तो किंष्किंधानरेश सुग्रीव के भी मित्र हैं। इस परंपरा को समझने वाले ही भारत के मन को समझ सकते हैं।

भारतीय समाज को लांछित करने के लिए उस पर सबसे बड़ा आरोप वर्ण व्यवस्था का है। जबकि वर्ण व्यवस्था एक वृत्ति थी, टेंपरामेंट थी। आपके स्वभाव, मन और इच्छा के अनुसार आप उसमें स्थापित होते थे। व्यावसायिक वृत्ति का व्यक्ति वहां क्षत्रिय बना रहने को मजबूर नहीं था, न ही किसी को अंतिम वर्ण में रहने की मजबूरी थी। अब ये चीजें काल बाह्य हैं। वर्ण व्यवस्था समाप्त है। जाति भी आज रूढ़ि बन गयी किंतु एक समय तक यह हमारे व्यवसाय से संबंधित थी। हमारे परिवार से हमें जातिगत संस्कार मिलते थे-जिनसे हम विशेषज्ञता प्राप्त कर 'जाब गारंटी' भी पाते थे। इसमें सामाजिक सुरक्षा थी और इसका सपोर्ट सिस्टम भी था। बढ़ई, लुहार, सोनार, केवट, माली, निषाद, बुनकर ये जातियां भर नहीं है। इनमें एक व्यावसायिक हुनर और दक्षता जुड़ी थी। गांवों की अर्थव्यवस्था इनके आधार पर चली और मजबूत रही। आज यह सारा कुछ उजड़ चुका है। हुनरमंद जातियां आज रोजगार कार्यालय में रोजगार के लिए पंजीयन करा रही हैं। जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था दोनों ही अब अपने मूल स्वरूप में काल बाह्य हो चुके हैं। अप्रासंगिक हो चुके हैं। ऐसे में जाति के गुण के बजाए, जाति की पहचान खास हो गयी है। इसमें भी कुछ गलत नहीं है। हर जाति का अपना इतिहास है, गौरव है और महापुरुष हैं। ऐसे में जाति भी ठीक है, जाति की पहचान भी ठीक है, पर जातिभेद ठीक नहीं है। जाति के आधार भेदभाव यह हमारी संस्कृति नहीं। यह मानवीय भी नहीं और सभ्य समाज के लिए जातिभेद कलंक ही है।

भारत के इतिहास में तमाम ऐसे पृष्ठ हैं, जिसमें हमारी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए समाज के हर वर्ग के लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। विदेशी आक्रामणों से जूझते हुए भी हमारे समाज ने अपनी सभ्यता और संस्कृति को जीवित रखा। बाद के कालखंड में विभेदकारी शासकों ने भारतीय समाज में विभाजन के बीज बोए क्योंकि उन्हें अपने राज को स्थाई बनाना था। लोगों के हाथ से हुनर छीन कर उन्हें दास बनाना उनका मकसद था। यह काम बिना बंटवारे की राजनीति से संभव नहीं था। भारत के सामने अपनी एकता को बचाने का एक ही मंत्र है, 'सबसे पहले भारत'। इसके साथ ही हमें अपने समाज में जोड़ने के सूत्र खोजने होगें। भारत विरोधी ताकतें तोड़ने के सूत्र खोज रही हैं, हमें जोड़ने के सूत्र खोजने होगें। किन कारणों से हमें साथ रहना है, वे क्या ऐतिहासिक और सामाजिक कारण हैं जिनके कारण भारत का होना जरूरी है। इन सवालों पर सोचना जरूरी है। अगर वे हमारे समाज को तोड़ने, विखंडित करने और जाति, पंथ के नाम पर लड़ाने के लिए सचेतन कोशिशें चला सकते हैं, तो हमें भी इस साजिश को समझकर सामने आना होगा। भारत का भला और बुरा भारत के लोग ही करेगें। इसका भला वे लोग ही करेंगें जिनकी मातृभूमि और पुण्यभूमि भारत है। वैचारिक गुलामी से मुक्त होकर, नई आंखों से दुनिया को देखना। अपने संकटों के हल तलाशना और विश्व मानवता को सुख के सूत्र देना हमारी जिम्मेदारी है ।

भारत अपनी लंबी गुलामी से उपजी इसी पीड़ा को आजतक भोग रहा है। कोई भी राष्ट्र इतने लंबे समय की गुलामी के बाद तमाम राष्ट्रों की तरह समाप्त हो जाता, किंतु भारत खड़ा है क्योंकि उसके पास परंपरा का उत्तराधिकार था। ऋषियों और संतों द्वारा दिया गया आध्यात्मिक उत्तराधिकार था। भक्ति ने भारत को हमेशा बचाया और बदला है। हमारी संत परंपरा हमारी जड़ों में एकता और समरसता के सूत्र पिरोती रही है। उनकी शरण में भारत खुद को तलाशता रहा है और सामने खड़े प्रश्नों से मुक्ति पाता रहा है। कुंभ जैसे आयोजन उसके नवपरिष्कार का अवसर देते रहे हैं, तो समाज में प्रवास कर संत शक्ति उसकी शक्ति को संगठित करती रही है। आज समरसता के मंत्रदृष्टा अनेक सामाजिक संगठन भी सक्रिय होकर अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। भारत जाग रहा, अपना पुर्नअविष्कार कर रहा है। अपनी सांस्कृतिक धारा से जुड़कर अपने संकटों के हल तलाश रहा है। यही यात्रा समरसता की वाहक भी और प्रस्थान बिंदु भी। सामाजिक एकता और सामाजिक समरता के बिना हम 'एक भारत और श्रेष्ठ भारत' नहीं बना सकते। इसलिए एकत्व के तत्व खोजना और मनों को जीतना हमारी कोशिश होनी चाहिए। यही बात 'भारत' को 'समर्थ भारत' बनाएगी।

बांग्लादेश में नई सरकार और मुख्य विपक्षी पार्टी के इरादे

नीरज कुमार दुबे

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना का भारत में रहना बांग्लादेश की नई सरकार और वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी को बिल्कुल नहीं भा रहा है। इसलिए वह भारत को चेतावनी देने में लग गये हैं। हम आपको बता दें कि अपदस्थ शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी की कट्टर प्रतिद्वंद्वी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने कहा है कि भारत में रहने का पूर्व प्रधानमंत्री का फैसला पूरी तरह से उनका और भारतीय अधिकारियों का है। बीएनपी ने लेकिन आगाह किया कि बांग्लादेश के लोग इसे अच्छे नजरिए से नहीं देखेंगे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रवक्ता अमीर खसरू महमूद चौधरी ने कहा, ''अभी, वह (हसीना) बांग्लादेश में हत्याओं और लोगों को जबरन गायब करने से लेकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार जैसे कई अपराधों में सबसे वांछित व्यक्ति हैं।'' महमूद चौधरी ने कहा कि यह ''खुद हसीना और भारत सरकार का निर्णय है कि उन्हें पड़ोसी देश में रहना चाहिए या नहीं।'' बीएनपी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली स्थायी समिति के सदस्य महमूद चौधरी ने कहा, ''फिर भी, बांग्लादेश के लोग सोचते हैं कि भारतीय अधिकारियों को उनकी भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए।'' महमूद चौधरी ने कहा, ''लोग (बांग्लादेश में) इसे (हसीना के भारत में रहने) को अच्छे नजरिए से नहीं देखेंगे।%% वहीं दूसरी ओर, बांग्लादेश की नवगठित अंतरिम सरकार में विदेश मंत्री की भूमिका में आये तौहीद हुसैन ने 'बड़े देशों' के साथ ढाका के संबंधों में 'संतुलन' बनाये रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार एवं पूर्व विदेश सचिव मोहम्मद तौहीद हुसैन ने संवाददाताओं से कहा कि कानून एवं व्यवस्था बहाल करना इस समय अंतरिम सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है तथा पहला लक्ष्य हासिल हो जाने के बाद अन्य कार्य भी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को सभी देशों के साथ अच्छे संबंध रखने की जरूरत है। तौहीद हुसैन ने किसी देश का नाम लिए बगैर कहा, ''हम सभी के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। हमें बड़े देशों के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है।'' हम आपको बता दें कि तौहीद हुसैन को भारत के बारे में मिश्रित विचार रखने के लिए जाना जाता है, वे एक तरफ ढाका के लिए भारत के महत्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश के हितों के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाते हैं। हुसैन ने पिछले साल एक व्याख्यान में कहा था कि पिछले 15 वर्षों में बांग्लादेश के हितों की भारत ने रक्षा नहीं की। उन्होंने कहा था कि यही कारण है कि भारत के साथ संबंध को आदर्श नहीं माना जा सकता। हम आपको बता दें कि भारत वर्षों से कहता रहा है कि बांग्लादेश के साथ उसके द्विपक्षीय संबंध सबके लिए आदर्श की तरह है। तौहीद हुसैन मानते हैं कि बांग्लादेश के संबंध अच्छे तभी होते हैं जब ढाका में खालिदा जिया के नेतृत्व वाली अवामी लीग की सरकार हो और दिल्ली में कांग्रेस की।

कौन होगा स्टालिन का उत्तराधिकारी?

आदिति फडणीस

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अगस्त के आखिर में प्रदेश के लिए निवेश जुटाने अमेरिका जाएंगे। वह करीब तीन सप्ताह तक विदेश में रहेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें कुछ नया नहीं है और अन्य मुख्यमंत्रियों की तरह वह भी प्रवासियों को लुभाने जा रहे हैं। परंतु इतने समय के लिए बाहर रहने पर अपनी जगह राज्य की बागडोर संभालने के लिए किसी व्यक्ति का चयन उत्तराधिकारी के चयन में बदल सकता है। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में अब दो वर्ष से भी कम बचे हैं (प्रदेश में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं), इसलिए उन पर दबाव होना स्वाभाविक है।

सबकी नजरें उनके बेटे उदयनिधि पर टिकी हैं, जो फिलहाल राज्य में द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) सरकार में खेल मंत्री हैं। सरकार में अन्य मंत्रियों का कहना है कि उदयनिधि को पहले उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। ऐसे लोगों में उच्च शिक्षा और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री आर एस राजकन्नपन और आवास एवं शहरी विकास मंत्री एस मुत्तुस्वामी जैसे लोग शामिल हैं। ऐसा बोलने वालों में सबसे नया नाम है नागर प्रशासन मंत्री केएन नेहरू का।

राजकन्नपन पहले द्रमुक छोड़कर अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक में चले गए थे मगर पार्टी में लौट आए हैं और यह जताने के लिए अधीर हुए जा रहे हैं कि पार्टी के साथ उनका जोड़ अब एकदम पक्का है। इस माह के आरंभ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने उदयनिधि को उप मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। उसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी बात में संशोधन किया और कहा कि लोग उन्हें उप मुख्यमंत्री कह सकते हैं लेकिन '19 अगस्त' के बाद। मुत्तुस्वामी भी पहले अन्नाद्रमुक में ही थे मगर वह 2010 में करुणानिधि के जीवित रहते ही द्रमुक में शामिल हो गए थे। उन्होंने भी उप मुख्यमंत्री पद के लिए उदयनिधि का नाम लिया है। परंतु नेहरू को गंभीरता से लेना होगा। वह त्रिची

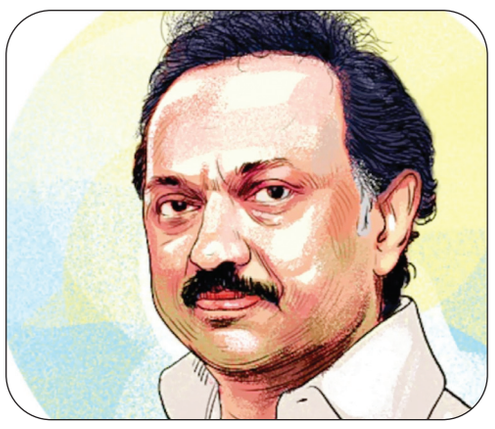

से पांच बार के विधायक हैं। वह कभी पार्टी छोड़कर नहीं गए हालांकि स्टालिन के साथ भी उनके मतभेद रहे हैं, जिन्हें वह राजनीति में देर से आने वाला व्यक्ति मानते हैं।

बहरहाल लोक सभा चुनावों के बाद द्रमुक में पार्टी के विस्तार के लिए सुझाव देने हेतु एक समिति बनाई गई, जिसमें उन्हें रखा गया था। इससे लगता है कि सब कुछ भुला दिया गया है और उन्हें माफ कर दिया गया है। लेकिन स्पष्ट है कि उदयनिधि के मामले में किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले नेहरू वही गलती नहीं दोहराना चाहते। उन्होंने भी कहा कि पार्टी कार्यकर्ता उदयनिधि को उप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और ऐसा हुआ तो 'हम सब खुश होंगे।' किंतु उन्होंने साथ में यह भी कहा कि स्टालिन 'किसी को भी उप मुख्यमंत्री' बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

अब कुछ बातें उदयनिधि के बारे में भी। सनातन धर्म पर अपनी टिप्पणी के बाद वह देश भर में सुर्खियों में आ गए। उन्होंने सनातन धर्म को जाति व्यवस्था के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराते हुए उसकी तुलना संक्रामक रोग से कर दी और उसका सफाया करना जरूरी बताया। इस पर मद्रास उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी खिंचाई की मगर उदयनिधि ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और वह देश भर की अदालतों में मुकदमे लड़ रहे हैं। उन्होंने तमिल फिल्मों में अभिनय भी किया, जिसमें उन्हें थोड़ी-बहुत सफलता मिली। उन्होंने फिल्म निर्माण कंपनी रेड जाइंट्स भी शुरू की और 2021 के विधानसभा चुनावों के समय राजनीति में उतर गए। वह चेन्नई के चेपक-तिरुवल्लिकेनी विधानसभा क्षेत्र से चुने गए।

किंतु स्टालिन को शायद खुद ही अपने पुत्र की स्वीकार्यता और गंभीरता पर संदेह है। वह एक से ज्यादा बार कह चुके हैं कि उदयनिधि अभी इस जिम्मेदारी के लिए 'तैयार' नहीं हैं। मगर वह यह भी मानते हैं कि पार्टी में उनका कद बढ़ाने की 'मांग बढ़ी' है। द्रमुक के जनक एम करुणानिधि ने स्टालिन को अपने मंत्रिमंडल में तब शामिल किया जब वह 50 वर्ष की उम्र पार कर चुके थे। 2009 में जब उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया तब वह 55 वर्ष के थे। करुणानिधि 2018 में निधन तक पार्टी के मुखिया बने रहे।

ऐसे में सवाल उठता है कि अगर उदयनिधि नहीं तो भला कौन? इसके जवाब में 86 वर्ष के दुरईमुरुगन का नाम उठता है, जो अभी जल संसाधन मंत्री हैं। उनकी उम्र से चिंता नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस उम्र में भी उनके बाल पूरी तरह काले हैं। अगस्त में बतौर विधायक उनके 53 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वह पहली बार 1971 में कटपडी विधानसभा से जीते और आठ बार उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह दो बार रानीपेट से भी विधायक रहे। पार्टी में कुछ ही लोग हैं जो उनकी वरिष्ठता या वफादारी को चुनौती दे सकते हैं।

परंतु उदयनिधि को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता है। उनसे वरिष्ठ लोग सोच सकते हैं कि उन्हें एक नेता के रूप में अभी और मंझना है। किंतु कांग्रेस जैसे गठबंधन साझेदार के नेता भी मानते हैं कि वह उस पार्टी में उत्तराधिकारी के रूप में स्वाभाविक पसंद होंगे, जहां उत्तराधिकार का संघर्ष किसी लंबे धारावाहिक से कम नहीं चलता। द्रमुक की राजनीति हमेशा दिलचस्प होती है और आने वाले दिनों में यह और रोचक होने जा रही है।

सियासत ने बढ़ाई जाति की खाई?

उमेश चतुर्वेदी

भारतीय राजनीति और समाज में जाति बहुत पेचीदा मुद्दा रहा है। जाति व्यवस्था को सामाजिक कोढ़ बताने वालों का मानना था कि विकास और आधुनिकता के आने से जाति व्यवस्था अपने आप टूटती जाएगी। गांधी मानते थे कि अछूतोद्धार के जरिए समाज में बराबरी का संदेश जाएगा। उन्होंने इसकी कोशिश भी की। दूसरी तरफ बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर मानते थे कि सामाजिक विकास यात्रा में पीछे छूट गए लोगों को आरक्षण देकर पहले सबल बनाया जाना चाहिए। वह तबका सबल होगा तो जाति व्यवस्था में बराबरी का भाव आएगा।

लोहिया सोचते थे कि पिछड़ों को आर्थिक रूप से ताकतवर बनाकर आगे लाया जाए तो सामाजिक समानता का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। कुछ ऐसी ही सोच दीनदयाल उपाध्याय की भी रही। लेकिन बहुजन आंदोलन के अगुआ कांशीराम की मान्यता रही कि पिछड़ों और दलितों को सत्ता मिले तभी जाति टूटेगी।

चारों वैचारिकी के आधार पर देखें तो सामाजिक रूप से जाति टूटती नजर आ रही है, लेकिन जैसे-जैसे आरक्षण की राजनीति आंबेडकर की बुनियादी सोच से आगे बढ़ने लगी, राजनीतिक रूप से जातियां अपने-अपने दायरे में और मजबूत होती गईं। 'जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी' की सोच बढ़ने लगी। इसलिए हर जाति नए सिरे से गोलबंद होने लगी। अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने और बढ़ाने के लिए ये जातियां अपने किले को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत करने लगीं। वोट बैंक की राजनीति ने इस प्रक्रिया को बढ़ावा दिया।

सत्ता के लिए बहुमत हासिल करने के लक्ष्य को लेकर लगातार सक्रिय राजनीति ने जातीय समूहों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में उनकी मांगों को उछालना शुरू किया। हर राजनीतिक समूह अपने हिसाब से अपनी समर्थक जातियों की राजनीतिक मांगों को जायज ठहराने लगा। इस पूरी प्रक्रिया में सामाजिक रूप से जाति को तोड़ने की सोच पीछे छूटती चली गई।

दिलचस्प यह है कि जब कोई जातीय समूह किसी खास राजनीतिक ताकत का साथ छोड़ने लगा तो उसके हक और अधिकारों की मांग उस राजनीतिक ताकत के लिए गौण होने लगी। पूरी भारतीय राजनीति इसी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रही है।

भारतीय संविधान में दलितों और आदिवासी समूहों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करते वक्त आंबेडकर ने इसे अनंतकाल तक चलाने से चेताया था। संविधान में शुरुआती दस साल के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था रखी गई थी। लेकिन जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था ना सिर्फ आंबेडकर की सोच से आगे निकल गई है, बल्कि वह अनंतकाल तक चलते रहने के लिए अभिशप्त है। जाति जनगणना की मांग राजनीतिक समूहों द्वारा जातीय समूहों को यह यकीन दिलाने की कोशिश है कि वे उनके लक्ष्य के साथ खड़े हैं।

चाहे गांधी रहे हों या आंबेडकर या फिर लोहिया, उनके विचारों और सिद्धांतों का बुनियादी मकसद सत्ता की राजनीति नहीं, सामाजिक समानता के जरिए भारतीय समाज का निर्माण था। लेकिन उनके नाम पर राजनीति करने वाले आधुनिक समूहों के साथ यह बात नहीं दिखती। समाजवादी धारा की मौजूदा राजनीति की प्रभावी ताकतों के पास भारतीय समाज बनाने का कोई ठोस सामाजिक कार्यक्रम नहीं है। उनमें जातीय उन्माद बढ़ाने और फैलाने का भाव ज्यादा नजर आता है। कांग्रेस की राजनीति अतीत में ऐसी अतिवादी नहीं रही है, लेकिन अब उसकी भी राजनीति उसी राह पर चल रही है।

गौर करने की बात है कि जिन सवर्ण जातियों के खिलाफ बाकी जातियों को गुस्से से भरने में ये शक्तियां मशगूल हैं, उन्हीं जातीय समूहों में कुछ ऐसी जातियां भी हैं, जिनकी दोयम हैसियत रही है। उदाहरण के लिए, ब्राह्मणों में महाब्राह्मण और शाकद्वीपीय समुदाय को लिया जा सकता है, जिनसे सामान्य ब्राह्मण समाज भी परहेज करता रहा है। क्षत्रिय और बनिया के बीच भी ऐसी कई छोटे समुदाय हैं, जो मौजूदा जातीय विमर्श में पिछड़े नजर आते हैं। लेकिन इस राजनीति को इस ओर ध्यान देने की फुरसत नहीं है। बेहतर होता कि यह राजनीति इस नजरिए से भी सोचती।

सच तो यह है कि जब भी जाति व्यवस्था कुछ कमजोर पड़ती दिखती है, राजनीति उसकी दरार को और बढ़ाने के लिए आगे आ जाती है। जातीय समूह भी अपने पारंपरिक भाईचारे को भूल अपने पड़ोस के ही जातीय समुदाय के खिलाफ राजनीति की ओर से पकड़ाई गई तलवार लेकर निकल पड़ते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आखिरकार सामाजिक ताना बाना ही छिन्न-भिन्न होता है। हालांकि हर राजनीतिक समूह इसी ताने-बाने को बनाए रखना अपना उद्देश्य भी बताता है।

संसद में अनुराग ठाकुर द्वारा राहुल गांधी की जाति का सवाल उठाने पर उठे राजनीतिक बवाल के बीच कुछ सवाल भी बनते हैं। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी या अखिलेश यादव ने कभी किसी की जाति नहीं पूछी? अपनी भारत यात्रा के दौरान ही राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे तो वहां एक रिपोर्टर ने उनसे कुछ असहज सा सवाल पूछ लिया, जिस पर उन्होंने उससे जाति पूछ ली थी। इसी तरह अखिलेश यादव से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले ही साल लखनऊ में एक रिपोर्टर ने असहज सा सवाल पूछ लिया था, तो उन्होंने भी उस रिपोर्टर को जाति पूछकर जलील किया था।

सार्वजनिक जीवन बिताने वालों से उम्मीद की जाती है कि वह दूसरों से जैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, वैसा ही व्यवहार खुद भी करें। अखिलेश हों या कांग्रेस, उनकी प्रतिक्रियाओं से उनकी चिढ़ दिख रही है। इसे राजनीति में कथनी और करनी के अंतर का एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है।

पड़ोसी देशों का विकास भारत के बिना असंभव

प्रो सतीश कुमार

बांग्लादेश के हालिया घटनाक्रम के बाद यह प्रश्न उठने लगा है कि क्या भारत की 'पड़ोसी प्रथम' की नीति हाशिये पर आ गयी है। दो साल पहले श्रीलंका में ऐसा ही कुछ हुआ था, जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। मालदीव में भारत विरोध की लहर समय-समय पर गूंजती है। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। पाकिस्तान 1947 से भारत विरोध के जरिये अपनी पतवार को खींचने की कोशिश में है। अफगानिस्तान में तालिबान की पैठ बनाने के बाद भारत का रोडमैप सीमित हुआ है। प्रश्न उठना लाजिमी है कि क्या यह भारत की विदेश नीति की उम्मीदों पर काली घटा का विस्तार है या समय का एक दौर है, जिसका कोई विशेष महत्व नहीं है। विदेश नीति और पड़ोसी देशों के संदर्भ में यह स्थापित सत्य है कि पड़ोसी देशों का आर्थिक विकास और उनकी राजनीतिक स्थिरता भारत के बिना संभव नहीं है, चाहे इन देशों को मदद अमेरिका से मिले या चीन से। बांग्लादेश ने पिछले डेढ़ दशक में इस बात की पुष्टि दुनिया के सामने कर दी है। भारत के कारण उसकी प्रति व्यक्ति आय एक समय भारत से बेहतर हो गयी थी। क्या ऐसा अमेरिका या चीन के अनुदान से हो सकता था? अगर अनुदान की राशि से अमीर होना होता, तो पाकिस्तान शीत युद्ध के दौरान ही अमेरिकी पैसे से ऐसा हो चुका होता। पिछले पांच दशक से चीन के सहयोग से पाकिस्तान चल रहा है। इसके बावजूद उसकी आर्थिक तंगी बढ़ती जा रही है। यह प्रश्न भी है कि क्या भारत पड़ोसी देशों के बिना दुनिया की अहम शक्ति बन सकता है। भारत की शक्ति उसकी आर्थिक क्षमता है। कोरोना महामारी की विपदा में भी भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं थमी। आर्थिक विशेषज्ञ यह मानते है कि आत्मनिर्भर भारत एक नये विकसित भारत की रूपरेखा बनाने में सक्षम होगा। भारत अपने व्यापार को विकेंद्रित भी कर रहा है। किसी एक नाव पर आश्रित होना घाटे का सौदा होगा। इसलिए रक्षा क्षेत्र में अन्य देशों की नयी टीम खोजी जा रही है। हरित ऊर्जा में भी भारत चीन से हटकर यूरोप के साथ अपने समीकरण को जोड़ने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ में कई ऐसे देश हैं, जिनके साथ भारत व्यापार बढ़ा रहा है। ऐसी हालत में भारत की तुलना में पड़ोसी देशों की संकीर्णता और हठधर्मिता उनके लिए ज्यादा नुकसानदेह होगी। बांग्लादेश में भारत की सोच को ठुकराया जा रहा है। जो गलती पाकिस्तान ने की थी, वही बांग्लादेश में दोहरायी जा रही है। भारत संवाद के जरिये बेहतरी की कोशिश करता रहा है, जिसमें कोई मजबूत और कोई कमजोर नहीं होगा। भारतीय संस्कृति की धारणा एक नये विश्व को बनाने का आधार बन रही है। हिंदू संस्कृति का जो विरोध बांग्लादेश में हो रहा है, वह एक सुनियोजित नाटक का हिस्सा है। वर्तमान शासक मोहम्मद यूनुस कोई फरिश्ता नहीं हैं। उनकी जन्मपत्री सबके सामने है। उनके पीछे कौन है, वह भी सबको मालूम है। हिंदू समुदाय बांग्लादेश में निरंतर हाशिये पर रहा है। हर राजनीतिक उथल-पुथल का दंश इस समुदाय को झेलना पड़ता है। कई ऐसे दर्द भरे दास्तान हैं, जो किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हजम कर पाना संभव नहीं है। विडंबना यह रही है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध में कोई अंतरराष्ट्रीय आवाज नहीं उठी है। बांग्लादेश में इस अत्याचार का एक आर्थिक सिद्धांत है। लाखों हिंदुओं की जमीन और संपत्ति हड़पने के लिए वहां कानून बनाये जाते रहे हैं, जिससे परेशान होकर वे बांग्लादेश छोड़ने के लिए विवश हो जाएं। बांग्लादेश की आबादी में हिंदू लगभग आठ प्रतिशत हैं, जो उस मुस्लिम बहुल राष्ट्र का सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है। पिछले 10 वर्षों में 15 बार शेख हसीना भारत के प्रधानमंत्री से मिल चुकी थीं। बिजली योजना से लेकर बहुमुखी परियोजनाओं के लिए प्रयास हो रहे थे। भारत के पूर्वोत्तर की कड़ी सीधा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। भारत बिम्सटेक पहल को मजबूत करना चाहता है, जिसमें बांग्लादेश एक अहम कड़ी है। लेकिन राजनीतिक समीकरण बदलने के साथ व्यापार की धारा और दिशा भी बदल जायेगी। वहां कट्टरपंथी ताकतें सर उठाने लगी हैं। बेगम खालिदा जिया दशकों से पाकिस्तान की भाषा बोलती रही हैं। अमेरिका के लिए लोकतंत्र और आतंकवाद एक मोहरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। साल 2021 और 2023 में जब अमेरिका में लोकतंत्र पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुए थे, उसमें पाकिस्तान को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन बांग्लादेश को नहीं बुलाया गया था।

सौन्दर्य के संसार में खूबसूरत करियर

खूबसूरत दिखना हर कोई चाहता है। लोगों की यही चाहत ऐसे बहुत से रोजगार पैदा कर जाती है, जिसकी आमतौर पर सामान्य छात्र कल्पना नहीं करता। कॉस्मेटोलॉजी ऐसा ही क्षेत्र है। इसमें अनेक शाखाएं हैं, जहां भविष्य की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। आप हेयर स्टाइलिस्ट, शैम्पू टेक्नीशियन, नख प्रसाधक, इस्थेटिशियन, ब्यूटी थेरेपिस्ट, नेल टेक्नीशियन और इलेक्ट्रोलॉजिस्ट तक बन सकते हैं और जॉब के रूप में हजारों तथा खुद का काम करके लाखों कमा सकते हैं।

सुन्दर दिखने की चाहत और उसके लिए तरह-तरह के नुस्खों की आजमाइश जोरों पर है। इसके लिए बाजार में सौन्दर्य प्रसाधनों व लाइफ स्टाइल के उत्पादों की बाढ़ सी आ गई है। शेविंग क्रीम हो या टूथ पेस्ट, फेस क्रीम, स्क्रीन क्रीम या फिर शैम्पू, साबुन और तेल-ये सभी आम जीवन की जरूरतों में शामिल हैं। बाजार में रोजमर्रा की मांग ने इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी खूब पैदा किए हैं। कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स इन अवसरों के बीच ही ले जाता है। इसकी मांग को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय में भी इस कोर्स को करवाया जा रहा है।

कॉस्मेटोलॉजी के रंग

इस कोर्स में छात्रों को पहले कॉस्मेटोलॉजी की विभिन्न ब्रांच और उसके विविध रूपों की जानकारी दी जाती है। ये ब्रांच हैं हेयर स्टाइलिस्ट, शैम्पू टेक्नीशियन, नख प्रसाधक, इस्थेटिशियन, ब्यूटी थेरेपिस्ट, नेल टेक्नीशियन और इलेक्ट्रोलॉजिस्ट। इसके बाद इन क्षेत्रों में काम आने वाले विभिन्न प्रोडक्ट्स के निर्माण के बारे में बताया जाता है। मसलन शेविंग क्रीम, टूथ ब्रश, पेस्ट, फेस क्रीम, सन्सक्रीम, नेल पॉलिश आदि। कोर्स से जुड़े विशेषज्ञों की मानें तो लाइफ स्टाइल और सौन्दर्य प्रसाधन से जुड़े जितने भी प्रोडक्ट प्रचलन में हैं, चाहे वे त्वचा संबंधी हों या आंख, नाक, कान, बाल, मुंह या शरीर के किसी और अंग से, इन सबके बारे में इस कोर्स में बताया जाता है। हेयर स्टाइलिस्ट को बालों के विभिन्न रूप, उनकी कटिंग और उनमें काम आने वाले कैमिकल्स की जानकारी दी जाती है। बालों को सुंदर बनाने की कला से भी रूबरू कराया जाता है।

शैम्पू टेक्नीशियन को आमतौर पर शैम्पू बनाने की विधियां, उसमें इस्तेमाल होने वाले रसायन और उसके इस्तेमाल की तरकीबें बताई जाती हैं। नख प्रसाधन के क्षेत्र में हाथ और पैर को सुन्दर बनाने वाली पॉलिश और क्रीम आदि के बारे में बताया जाता है। साथ ही देखभाल के बारे में जानकारी दी जाती है।

इस्थेटिशियन को आमतौर पर त्वचा की देखभाल की कला सिखाई जाती है। उसे नई तकनीक के इस्तेमाल से अंग लेपन, फेशियल मसाज आदि से अवगत कराया जाता है। इसमें दक्ष इस्थेटिशियन चाहे तो स्वतंत्र रूप से सैलून या स्पा में काम कर सकता है। वह चाहे तो किसी डॉक्टर को इस क्षेत्र की प्रैक्टिस में सहायता भी प्रदान कर सकता है। इस्थेटिशियन को त्वचा की देखभाल संबंधी उत्पाद की जानकारी के साथ-साथ उसके नफे-नुकसान के बारे में बताया जाता है। त्वचा की पूरी तरह से देखभाल के कारण इसे स्किन केयर थेरेपिस्ट भी कहा जाता है।

ब्यूटी थेरेपिस्ट को मशीन द्वारा बालों को हटाना, आंखों की पुतलियां सजाना, ठीक करना जैसी चीजों के बारे में दक्ष बनाया जाता है। इलेक्ट्रोलॉजिस्ट को इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। विद्युत तरंगों से लैस मशीन से बाल को उखाड़ना या उसे उगाना जैसे काम इसमें बखूबी किए जाते हैं। कोर्स में छात्रों को सामान्य मेडिसिन की जानकारी भी दी जाती है। हालांकि डॉक्टर की तरह इलाज करना उसका काम नहीं होता। उसे सौन्दर्य प्रसाधन से जुड़े प्रोडक्ट्स का क्या-क्या असर होगा, यह भी पढ़ाया जाता है। मोटापा बढ़ने पर वजन कम करने और आकर्षक लुक व सुडौल शरीर कैसे बने, इसका भी ज्ञान दिया जाता है। यही नहीं, उसे मानव साइकोलॉजी का भी पाठ पढ़ाया जाता है। कोर्स में एनेलिटिकल कैमिस्ट्री का भी पाठ शामिल है।

दाखिले की प्रक्रिया

दाखिले के लिए कहीं 12वीं पास तो कहीं बीएससी या स्नातक की मांग की जाती है। कैमिस्ट्री की पढ़ाई करने वालों के लिए यह और फायदेमंद हो जाता है। यह कोर्स सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों तरह के संस्थानों में चल रहे हैं।

रोजगार कहां

कोर्स को करने के बाद छात्र चाहे तो खुद बॉडी केयर सेंटर खोल सकते हैं। दिल्ली जैसे शहर में इस तरह के सेंटर से लोग प्रति माह हजारों रुपए कमा रहे हैं। आप ब्यूटीशियन के लिए बतौर कंसलटेंट काम कर सकते हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों में भी काफी अवसर हैं। छात्र चाहे तो कॉस्मेटिक निर्माण की यूनिट भी लगा सकता है। जहां तक आय का सवाल है, कोई चाहे तो किसी के यहां काम करके 20 से 30 हजार रुपए भी कमा सकता है और स्वरोजगार में लाख, दो लाख रुपए महीना भी।

क्या कहता है आपका एप्टीटयूड

विषय अनेक और करियर भी अनेक, इतने कि किसे चुनें, किसे नहीं। इसी ऊहापोह में छात्र भटक कर रह जाते हैं। अपनी दुविधा लेकर काउंसलरों के पास आने वाले छात्रों के आंकड़े बताते हैं कि हाल-फिलहाल में छात्रों में यह असमंजस की स्थिति कहीं ज्यादा बढ़ी है। आपके इस असमंजस को सही दिशा दे सकता है एप्टीटयूड टैस्ट। किस-किस तरह के हैं ये एप्टीटयूड टैस्ट?

अमोल संगीतज्ञ बनना चाहता है, लेकिन उसके माता-पिता उसे इंजीनियर के रूप में देखना चाहते हैं। पिता और अमोल के बीच करियर के चुनाव को लेकर काफी दिन तक खींचतान चलती रही। घर में इस कलह को दूर करने के लिए उसे काउंसलरों ने एप्टीटयूड टैस्ट कराने की सलाह दी। अमोल के एप्टीटयूड टैस्ट के बाद ही यह पता लगाया गया कि वह एक सफल संगीतज्ञ बन सकता है। टैस्ट में उसमें क्रिएटिव इनोवेशन के लक्षण ज्यादा पाए गये। इस क्षेत्र में उसकी विशेष रुचि भी देखी गई। अमोल अकेला ऐसा छात्र नहीं। उसकी तरह कई और भी छात्र हैं, जिनके जीवन को सही दिशा देने के लिए माता-पिता अब एप्टीटयूड टैस्ट कराने लगे हैं। किसी व्यक्ति की क्षमता का आकलन एप्टीटयूड टैस्ट से ही हो पाता है। उसमें इंजीनियर बनने की क्षमता है या ड्राइवर या कलाकार, इसे पता लगाने का सटीक उपाय है एप्टीटयूड टैस्ट। दिल्ली विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रो. एनके चड्ढा कहते हैं, करियर का सही चुनाव और उसमें मौजूद क्षमता के आकलन के लिए एप्टीटयूड के साथ बच्चे की रुचि भी देखी जाती है। ऐसा करने पर करियर के चुनाव में खासी मदद मिलती है। एप्टीटयूड और इंटरेस्ट, दोनों एक-दूसरे के साथ जुड़े हैं और साथ-साथ चलते हैं। अगर एक है और दूसरा नहीं तो करियर को सही दिशा नहीं मिलती।

काउंसलर गीतांजलि कुमार करियर और जीवन को सही दिशा देने में एप्टीटयूड और इंटरेस्ट के साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व और शारीरिक क्षमता को भी एक कड़ी मानती हैं। वह कहती हैं, इन सबको मिला कर ही किसी को करियर या जीवन में कोई राह चुनने की सलाह दी जाती है। अगर किसी में किसी कार्य के प्रति एप्टीटयूड है, पर रुचि या करने की इच्छा नहीं तो उस दिशा में भेजना बेकार है। इसी तरह पहली दोनों चीजें हैं, लेकिन शारीरिक क्षमता या व्यक्तित्व नहीं तो ऐसे करियर के चुनाव की सलाह देना बेकार है। वह कहती हैं, व्यक्तित्व भी पॉजिटिव मोटिव देता है, इसलिए तीनों को देखना जरूरी है।

क्यों है जरूरी

एप्टीटयूड टैस्ट ही किसी छात्र या व्यक्ति के करियर और काम की दिशा बताता है। उसकी क्षमता और रुचि को बताता है। इसके बाद उसे सही प्रोफेशन चुनने की सलाह दी जाती है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर ऐसा नहीं होता तो अमुक व्यक्ति में आगे चल कर कुंठा का जन्म होता है। वह काम को एन्जॉय नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में उसके अंदर नकारात्मक सोच हावी हो जाती है। वह विध्वंसात्मक दिमाग का हो जाता है। उसमें पहचान का संकट भी पैदा होने लगता है। एप्टीटयूड, रुचि और व्यक्तित्व के हिसाब से काम नहीं मिलने पर वह अपने पेशे में उतना सक्षम साबित नहीं होता, जितना दूसरे लोग। ऐसे में वह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कई बार उलटे-सीधे हथकंडे भी अपनाता है। सफलता नहीं मिलने पर वह कई बार अवसाद की स्थिति में आ जाता है और आत्महत्या को मजबूर हो जाता है, इसलिए शिक्षण संस्थानों को सरकार ने बच्चों के करियर की दिशा तैयार करने को कहा है। शिक्षण संस्थाओं में करियर एंड काउंसलिंग सेंटर आए दिन इसी वजह से खोले जा रहे हैं। यह हर संस्थान और काम की जगह की जरूरत बनती जा रही है। प्रो. चड्ढा कहते हैं, भारत में इस तरह की समस्याओं के लिए निजी प्रैक्टिशनर की ओर से जगह-जगह नगरों व महानगरों में काउंसलिंग सेंटर खुल गए हैं, लेकिन इसे चलाने वाले लोग आमतौर पर क्वालिफाइड नहीं होते। काउंसलिंग के लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त है या नहीं, इसके लिए नेशनल एजेंसी बनी है। वह क्वालिफिकेशन तय करती है। गाइडलाइंस भी तैयार किए हैं।

एप्टीटयूड टैस्ट के रूप-रंग

लॉजिकल रीजनिंग- एप्टीटयूड टैस्ट के कई आयाम हैं, जिनमें एक है लॉजिकल रीजनिंग। इसके तहत कार्य-कारण संबंध पर जोर होता है। किसी व्यक्ति में मानसिक स्तर पर कैलकुलेशन की क्षमता कितनी है, इसका आकलन लॉजिकल रीजनिंग के माध्यम से किया जाता है। अगर वह लॉजिकल रीजनिंग में ज्यादा स्कोर करता है तो इससे पता चलता है कि वह कायदे-कानून में रह कर कठिन से कठिन समस्याओं को हल कर सकता है। इस क्षमता से लैस युवा मैनेजर, वैज्ञानिक और व्हाइट कॉलर जॉब में जाने के उपयुक्त होते हैं।

एब्सट्रेक्ट रीजनिंग - इसके तहत खरा उतरने वाला युवा बिखरी हुई चीजों को एकत्रित करके प्लान के साथ काम करने में विशेष हुनर रखता है। इसमें एप्टीटयूड किस तरफ जा रहा है, उसकी दिशा क्या है, वह एक एरिया से दूसरे एरिया में लिंक कर रहा है या नहीं, यह भी देखा जाता है। सिविल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बेहतर करने वाले युवाओं में एब्सट्रेक्ट रीजनिंग हल करने की क्षमता ज्यादा पाई जाती है।

न्यूमेरिकल रीजनिंग - यह किसी व्यक्ति की गणितीय क्षमता की जानकारी देता है। वह गुणा-भाग करने और सांख्यिकीय सवालों को हल करने की कितनी क्षमता रखता है, इसका आकलन इसके द्वारा किया जाता है। इसे देख कर ही उसे इस विषय या क्षेत्र से जुड़े करियर में जाने की सलाह दी जाती है। मसलन सीए, गणितज्ञ और लेखाकार आदि बनने के लिए न्यूमेरिकल रीजनिंग में बेहतर होना चाहिए।

आई-हैंड कोऑर्डिनेशन - आमतौर टेक्निकल काम मसलन ड्राइविंग हो, पायलट या फिर किसी मशीन को चलाने के लिए मशीनमैन हो, उसमें यह एप्टीटयूड जरूर होना चाहिए। इसमें कोई व्यक्ति हाथ, पैर व आंख को काम करते वक्त कितना केन्द्रित कर पाता है, यह देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति दुर्घटनाओं को कम करने में काफी मददगार साबित होता है। ड्राइवर, पायलट, मशीनमैन और मैकेनिकल जॉब के लिए यह एप्टीटयूड बढ़िया माना जाता है।

क्रिएटिव इनोवेशन - इसमें किसी व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता का आकलन किया जाता है। उसमें कलात्मक रुझान व रुचि का पता लगाया जाता है। आमतौर पर व्हाइट कॉलर जॉब में इस तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है। इसके तहत यह भी देखा जाता है कि वह निर्णय कितना शीघ्र और सही रूप में लेता है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। कोई व्यक्ति स्वभाव में अड़ियल तो नहीं है। अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का स्तर बेहतर है तो उसे उच्चतम पदों की जिम्मेदारी दी जाती है। इसमें उसके अंदर बड़प्पन कितना है, इसका आकलन भी किया जाता है। एप्टीटयूड टैस्ट में ओरिजनेलिटी और मौलिकता को भी देखा जाता है। ऐसे चंद ही व्यक्ति होते हैं, जो अलग किस्म के आइडिया से लैस होते हैं। इस टैस्ट में ओरिजनल आइडिया को देखा व समझा जाता है। इसे बहुविध सोच के रूप में भी देखा जाता है। यह गुण जिसमें है, उसमें अध्यापक, लेखक, अभिनेता, संगीतज्ञ और आविष्कारक बनने की क्षमता होती है।

प्रोफेशनल लाइफ में रख रहे हैं कदम अपनाएं ये टिप्स

कॉलेज लाइफ को अलविदा कहकर प्रोफेशनल वर्ल्ड में कदम रखने कम चुनौतीपूर्ण नहीं हैं। कई युवाओं के लिए कॉलेज ग्रेजुएशन पूरा होने और अपने पहले जॉब की शुरुआत काफी तनावपूर्ण होती है। कॉलेज पूरा करने के बाद आपको जॉब हंटिंग, इंटरव्यू देना होता है और वास्तविकता का सामना करना इतना आसान नहीं है। कॉलेज स्टूडेंट से एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉई बनने का यह ट्रांजिशन सफल बनाने के लिए कुछ बातों को समझना जरूरी है। इन मुद्दों को समझकर और उनके लिए तैयार रहकर इस बदलाव को आसान बना सकते हैं।

कॉलेज जाने और नौकरी पर जाने में बहुत फर्क है। आप जॉब में बंक नहीं मार सकते। आप पैसे देकर ट्यूशन नहीं ले रहे बल्कि आपको पे किया जा रहा है। इसलिए ट्यूशन की तरह मन न होने पर आप काम पर नहीं जाने का मन नहीं बना सकते। आपको नौकरी में आठ घंटे तो काम करना ही पड़ता है।

कॉलेज का समय प्रयोग का समय होता है। हम यहां थोड़ा गैर जिम्मेदार हुए तो चलेगा लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा नहीं है। कॉलेज में गैर जिम्मेदार होने का मतलब खराब ग्रेड लेकिन वर्कप्लेस पर अनप्रोफेशनल होना मतलब आपके नौकरी की छुट्टी। प्रोफेशनल का मतलब ही सेल्फ-स्टार्टर होता है। कॉलेज से ज्यादा डेडलाइन का सामना आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड में करना होगा।

ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपके दिमाग में अपना स्पष्ट करियर पाथ होना चाहिए लेकिन अगर आपका पहला जॉब अपनी योजना से मेल नहीं खाता है तो घबराइए नहीं।

कॉलेज छोड़ने और प्रोफेशनल दुनिया में कदम रखने में बहुत चीजें बदलती है। हां, अगर आप दोपहर तक सोते रहते हैं या देर रात फिल्में देखते हैं तो यह सब आपको बंद करना पड़ेगा। आपकी डाइट भी बदलेगी। लाइफस्टाइल के बदलावों के लिए तैयार रहें।

कॉलेज लाइफ खत्म होने का मतलब नहीं कि आपकी लाइफ से फन गायब हो गया। आप अभी भी ट्रेवल कर सकते हैं, दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं और नए व रोमांचक चीजें सीख सकते हैं। इस समय आपको देखना होगा कि किस तरह से मनोरंजन करें ताकि आप अपनी जॉब की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभा पाएं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

रक्षा मंत्री 23 से 26 अगस्त तक अमेरिका की यात्रा करेंगे

नईदिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार से अमेरिका की चार दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे तथा इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे। सिंह वाशिंगटन में अमेरिका के अपने समकक्ष लॉयड ऑस्टिन तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान समेत अन्य लोगों से बातचीत करेंगे। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि सिंह की ऑस्टिन से बातचीत में 31 एमक्यू-9बी प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की भारत की योजना, स्ट्राइकर इन्फैन्ट्री लड़ाकू वाहन का प्रस्तावित संयुक्त विनिर्माण और भारत में जीई एफ414 इंजन के सह-उत्पादन पर प्रमुखता से चर्चा होने की संभावना है। रक्षा मंत्रालय ने 23 से 26 अगस्त तक सिंह की अमेरिका यात्रा की घोषणा करते हुए कहा, ''इस यात्रा से भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और गहरी तथा मजबूत होने की संभावना है।''

राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने मानी हार!

जयपुर। आगामी राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने हार मान ली है! राजस्थान में राज्यसभा चुनाव हो रहा है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को प्रत्याशी घोषित किया है। रवनीत सिंह बिट्टू पूर्व कांग्रेसी सांसद हैं और लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का दामन थाम लिया था। हालांकि बिट्टू को आम चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा ने फिर भी मोदी सरकार में मंत्री पद दिया। इस बीच कांग्रेस की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में हम प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। भाजपा की जीत तय है। डोटासरा ने कहा कि पार्टी आगामी राज्यसभा चुनाव में राज्य में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। डोटासरा ने कहा कि पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) निर्वाचित प्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त में लिप्त है। डोटासरा ने कहा, हम उनकी (भाजपा) तरह दलालों पर निर्भर नहीं हैं।

राज्यसभा के लिए एनडीए के उम्मीदवारों ने किया नामांकन

पटना। राज्यसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए के दोनों उम्मीदवारों उपेंद्र कुशवाहा और मनन मिश्रा ने बुधवार को अपना-अपना नामांकन दाखिल किया। बिहार की दो सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन के लिए एनडीए के दोनों प्रत्याशी विधानसभा पहुंचे थे। सीएम नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व विजय कुमार सिन्हा समेत कई अन्य नेताओं की मौजूदगी में विधानसभा परिसर में नामांकन कार्य संपन्न किया गया। गौरतलब है कि एनडीए की तरफ से बिहार की दो सीटों पर आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा की ओर से मनन मिश्रा का नामांकन हुआ है। दरअसल, लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर से विवेक ठाकुर और राजद की मीसा भारती ने जीत हासिल की थी। दोनों पहले राज्यसभा के सदस्य थे। दोनों की जीत के बाद ये दो सीटें खाली हुई हैं जिसपर उपचुनाव कराया जा रहा है।

जम्मू-कश्मीर में नेकां-कांग्रेस के बीच होगा गठबंधन?

जम्मू। लोकसभा चुनाव की तर्ज पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में हो रहे पहले विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कांन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावनाएं तलाशने के लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सोमवार की रात श्रीनगर के एक सांच सितारा होटल में दोनों दलों के पांच-पांच नेताओं की मौजूदगी में बातचीत शुरू हुई। सब कुछ ठीक रहा तो अगले चार-पांच दिनों में गठबंधन की घोषणा हो जाएगी। सूत्रों ने बताया, दोनों पार्टियों के आलाकमान के निर्देश पर बातचीत का सिलसिला शुरू किया गया। इसके लिए कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा, कार्यकारी अध्यक्ष ताराचंद व रमण भल्ला तथा पूर्व अध्यक्ष जीए मीर व विकार रसूल वानी तथा नेकां से कश्मीर संभाग के अध्यक्ष नसीर असलम वानी, जम्मू संभाग के अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता, सकीना इट्टू, खालिक सुहरावर्दी तथा अतिरिक्त महासचिव अजय सडोत्रा को नामित किया गया है।

महाविकास अघाड़ी ने 24 को महाराष्ट्र बंद का किया आह्वान

मुंबई। बदलापुर घटना के विरोध में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने बुधवार को 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया। एमवीए ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के तीनों दल इस एक दिवसीय बंद में भाग लेंगे। इससे पहले बुधवार को एनसीपी (एससीपी) सांसद सुप्रिया सुले ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बदलापुर के एक किंडरगार्टन स्कूल में दो युवा लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न को लेकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे जिला स्थित एक स्कूल के शौचालय में चार वर्षीय दो बच्चियों से सफाईकर्मी द्वारा कथित यौन उत्पीड़न किये जाने के बाद, हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने बदलापुर रेलवे स्टेशन की पटरियों को अवरुद्ध कर दिया और विद्यालय परिसर में धावा बोल दिया। पुलिस ने रेल पटरियों पर मौजूद प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्च किया, जो पुलिसकर्मियों पर पथराव कर रहे थे।

दलित संगठनों के भारत बंद का विपक्षी दलों ने किया समर्थन

नईदिल्ली। बुधवार को पूरे देश में दलित संगठनों द्वारा एसी-एसटी एक्ट के समर्थन में भारत बंद आंदोलन को आयोजित किया गया था। इस हड़ताल के समर्थन में विपक्ष खुलकर सामने आया है जिसमें क्षेत्रियों दलों से लेकर राष्ट्रीय दल तक शामिल है। एक ओर जहां कांग्रेस, बीएसपी और आरजेडी ने इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है, वहीं, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बुधवार को आंदोलन के समर्थन में बयान दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण श्रेणियों में उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद को अपना समर्थन दिया।

उन्होंने कहा कि आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है और यह शोषितों और वंचितों में नई चेतना पैदा करेगा। सपा प्रमुख ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। यह शोषितों और वंचितों में नई चेतना पैदा करेगा और आरक्षण के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन एक लोकतांत्रिक अधिकार है।

अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार घोटालों और घोटालों के जरिए संविधान और लोगों के अधिकारों से छेड़छाड़ करती है तो जनता को सड़कों पर उतरना होगा। उन्होंने कहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पहले ही चेतावनी दी थी कि संविधान तभी कारगर होगा जब उसे लागू करने वालों की नीयत सही होगी। जब सत्ता में बैठी सरकारें धोखाधड़ी, घोटाले और घपलेबाजी करके संविधान और उसके द्वारा दिए गए अधिकारों से छेड़छाड़ करेंगी, तो जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जनांदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं।

इस भारत बंद विरोध प्रदर्शन का बसपा ने भी समर्थन किया है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने फैसले के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश दिखाया और कहा, इन समूहों के लोगों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश है। मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बीएसपी भारत बंद का समर्थन करती है क्योंकि 1 अगस्त 2024 को एससी/एसटी और क्रीमी लेयर के उप-वर्गीकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश है,

क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों द्वारा आरक्षण के खिलाफ साजिश और इसे अप्रभावी बनाने और अंततः इसे समाप्त करने के लिए उनकी मिलीभगत है।

गौरतलब है कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्यों के पास एससी और एसटी को उप-वर्गीकृत करने का अधिकार है और कहा कि संबंधित प्राधिकारी, यह तय करते समय कि क्या वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, मात्रात्मक प्रतिनिधित्व के आधार पर नहीं बल्कि प्रभावी प्रतिनिधित्व के आधार पर पर्याप्तता की गणना करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के बहुमत के फैसले से फैसला सुनाया कि एससी और एसटी आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति है। मामले में छह अलग-अलग राय दी गईं।

यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात जजों की बेंच ने सुनाया, जिसने ईवी चिन्नैया मामले में पहले के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं है क्योंकि एससी/एसटी समरूप वर्ग बनाते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा बेंच में जस्टिस बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे।

जस्टिस बीआर गवई ने सुझाव दिया कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भी क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति विकसित करे ताकि उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के लाभ से बाहर रखा जा सके। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने असहमति जताते हुए कहा कि वह बहुमत के फैसले से असहमत हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर किया हमला

मुंबई। मुंबई में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा पर परोक्ष हमला किया और कहा कि पार्टी एक जहर है जिसे पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है। सद्भावना दिवस के रूप में मनाए गए इस कार्यक्रम में शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाग लिया और कांग्रेस को भाजपा की तुलना में बेहतर सहयोगी बताया। ठाकरे ने पहली बार कांग्रेस का स्टोल पहना, जो राजनीतिक गठबंधनों में बदलाव का संकेत था।

खड़गे ने भाजपा पर नकारात्मक प्रभाव डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा जहर की तरह है। इसका स्वाद चखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसके परिणाम जानते हैं। इसे पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है। उन्होंने भाजपा को संविधान में संशोधन करने से रोकने के लिए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने राज्य सभा सहित

विधायी प्रभाव बनाए रखने के लिए राज्य विधानसभा चुनाव जीतने के महत्व को रेखांकित किया। खड़गे ने वक्फ भूमि के लिए संशोधन विधेयक और अनुबंध के आधार पर लेटरल एंट्री जैसे उदाहरणों का हवाला दिया और कहा, उन्होंने लेटरल एंट्री के फैसले को वापस ले लिया क्योंकि आप मजबूत हैं। अगर ऐसा नहीं होता, तो वे आरएसएस पृष्ठभूमि के लोगों की भर्ती करते।

पहली बार कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में शामिल हुए उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और भाजपा के बीच मतभेदों पर अपना रुख स्पष्ट किया। ठाकरे ने कहा, किसी व्यक्ति को समझने के बाद हमें खुद को बदलने की जरूरत है। मुझे एहसास हुआ है कि उन्होंने हमारा दुरुपयोग किया और अब हमें कमजोर करना शुरू कर दिया है। राजीव जी (पूर्व पीएम राजीव गांधी) और उनके बीच का अंतर स्पष्ट है। उन्होंने सराहना की कि कांग्रेस सरकारों ने उनके पिता बाल ठाकरे की कड़ी आलोचना के बावजूद कभी भी शिवसेना के खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं की।

ठाकरे ने कहा, बालासाहेब (ठाकरे) राजीव जी की कड़ी आलोचना करते थे, लेकिन मैंने कभी ईडी (प्रवर्तन निदेशालय), सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) और आयकर को किसी शिवसेना कार्यकर्ता के पीछे पड़ते नहीं देखा। उन्होंने संजय राउत जैसे शिवसेना (यूबीटी) नेताओं को निशाना बनाकर की जा रही केंद्रीय जांच का उल्लेख भाजपा के प्रतिशोधात्मक दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में किया।

भाजपा ने ममता बनर्जी से इस्तीफा देने की मांग की

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले ने अब राजनीतिक रुख ले लिया है। डॉक्टरों के साथ भाजपा के नेता भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बंगाल में विपक्षी पार्टी भाजपा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और लॉकेट चटर्जी ने प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने इस मामले में ममता सरकार की तीखी आलोचना की। भाजपा ने ममता बनर्जी से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की भी मांग की।

बंगाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया कि उन्हें ममता बनर्जी की सरकार पर भरोसा नहीं है और पुलिस कमिश्नर को तुरंत हटाया जाना चाहिए। ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य में एक के बाद एक महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। इसस साबित होता है कि ममता बनर्जी का प्रशासन पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए हमारी यह मांग है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हम पांच सितंबर तक प्रदर्शन करेंगे।

मुख्यमंत्री शिंदे ने विरोध को बताया राजनीति से प्रेरित

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को कहा कि दो किंडरगार्टन लड़कियों के कथित यौन शोषण मामले पर ठाणे जिले के बदलापुर में विरोध प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित था और इसका उद्देश्य राज्य सरकार को बदनाम करना था। मुद्दे को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकांश प्रदर्शनकारी बाहरी थे। पत्रकारों से बात करते हुए शिंदे ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि घटना पर राजनीति करने वालों को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विरोध राजनीति से प्रेरित था क्योंकि प्रदर्शनकारी स्थानीय निवासी नहीं थे। जो स्थानीय निवासी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे, उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य मंत्री गिरीश महाजन प्रदर्शनकारियों की सभी मांगों पर सहमत हैं लेकिन वे अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि वे सिर्फ सरकार को बदनाम करना चाहते थे। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब मंगलवार को बदलापुर शहर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, क्योंकि गुस्साए माता-पिता, स्थानीय निवासियों और अन्य लोगों ने रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध कर दिया और स्कूल में तोड़फोड़ की।

खेल
प्रमुख समाचार

आईसीसी ने बांग्लादेश से छीनी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी

नईदिल्ली। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप अब

यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश में हुई हिंसा और तख्तापलट के बाद देश के हालात ठीक नहीं है। जिसके बाद बांग्लादेश से विमेंस टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी छीन ली गई। अब 3 अक्टूबर से यूएई में 10 टीमों का विमेंस टूर्नामेंट खेला जाएगा। हालांकि, टूर्नामेंट के होस्टिंग राइट्स बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी के पास ही रहेंगे। मेजबानी के लिए श्रीलंका और जिम्बाब्वे भी रेस में थे, लेकिन आईसीसी ने यूएई को मेजबानी देने का फैसला किया। इससे पहले आईसीसी ने बीसीसीआई से मेजबानी करने को कहा लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह ने इससे इनकार कर दिया।

फिलहाल, आईसीसी ने बताया कि यूएई के दुबई और शारजाह स्टेडियम में टूर्नामेंट के सभी मैच कराए जाएंगे। टूर्नामेंट 3 से 20 अक्टूबर तक खेला जाना है।

पिछले कुछ सालों से यूएई को आईसीसी और ष्ट के कई टूर्नामेंट की मेजबानी मिल चुकी है। 2021 में कोरोना महामारी के कारण भारत के होस्टिंग राइट्स में मेंस टी20 वर्ल्ड कप यूएई में हुआ था। अब 4 साल के अंदर यूएई को दूसरे वर्ल्ड कप की मेजबानी मिल गई है। यूएई में एशियन क्रिकेट काउंसिल के 2 एशिया कप भी पिचले 6 साल में हुए हैं। 2018 में वनडे एशिया कप और 2022 में टी20 एशिया कप की मेजबानी यूएई को मिली थी। खास बात ये है कि यूएई के दुबई में आईसीसी का हेडक्वॉर्टर भी है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर बंद

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजारों में बुधवार को सत्र के अधिकांश भाग में किसी बड़े संकेत के अभाव के कारण कारोबार में सुस्ती रही। हालांकि, स्वस्थ्य शेयरों के नेतृत्व में धीमी गति से सुधार से बेंचमार्क इंडेक्स को हरे निशान पर स्थिर होने में मदद मिली। छोटी कंपनियों की अगुवाई करने वाला बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स ने 0.87 प्रतिशत की बढ़त हासिल की। वहीं, मझोली कंपनियों से जुड़ा बीएसई मिडकैप इंडेक्स 0.43 फीसदी चढ़ा। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 102.44 अंक या 0.13 प्रतिशत की बढ़त लेकर 80,905.30 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 80,626.38 और 80,952.83 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ एनएसई निफ्टी 71.35 अंक या 0.29 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,770.20 पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 24,654.50 और 24,787.95 के रेंज में कारोबार हुआ।

डिकेथलॉन भारत में 10 करोड़ यूरो का करेगा निवेश

नईदिल्ली। फ्रांस की खेल खुदरा कंपनी डिकेथलॉन की भारत में खुदरा कारोबार और विनिर्माण परिचालन का विस्तार करने के लिए अगले पांच साल में 10 करोड़ यूरो (करीब 933 करोड़ रुपये) का निवेश करने की योजना है। डिकेथलॉन इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) शंकर चटर्जी ने कहा कि कंपनी को उम्मीद है कि अगले तीन से पांच वर्षों में उसका कारोबार दोगुना हो जाएगा। उसकी योजना 190 स्टोर का नेटवर्क बनाने की है। विस्तार के तहत अगले पांच वर्षों में स्टोर की संख्या 90 से अधिक करने का लक्ष्य है। चटर्जी ने कहा, '' हमारा लक्ष्य 2026 तक डिकेथलॉन इंडिया के लिए घरेलू विनिर्माण को 85 प्रतिशत पर लाना है।'' डिकेथलॉन की योजना हर साल 10-15 नए स्टोर खोलने की है, जिससे ऑनलाइन बिक्री में तेजी आएगी और विस्तार के तहत स्थानीयकरण बढ़ेगा।

लार्सन एंड टुब्रो को महाराष्ट्र में मिला 'बड़ा' कॉन्ट्रैक्ट

नईदिल्ली। इंजीनियरिंग व निर्माण समूह लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) को महाराष्ट्र में एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक ''बड़ा'' ठेका मिला है। एलएंडटी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि ठेका एलएंडटी की परिवहन बुनियादी ढांचा इकाई को मिला है। कंपनी ने ठेके के वित्तीय विवरण का खुलासा नहीं किया। हालांकि, वह 2,500 करोड़ रुपये से 5,000 करोड़ रुपये तक के ठेकों को ''बड़ा'' बताती है। कंपनी सूचना के अनुसार, '' एलएंडटी को महाराष्ट्र में नवी मुंबई एअरपोर्ट इन्फ्लुएन्स नोटिफाइड एरिया (एनआईए) परियोजना के तहत नगर नियोजन योजना दो से सात में एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास का ठेका मिला है।'' ठेका शहर एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडको) से मिला है। यह सड़कों के एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास, विभिन्न प्रमुख तथा लघु संरचनाओं के निर्माण व संबद्ध विद्युत कार्यों से जुड़ा है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने सेबी को किया भुगतान

नईदिल्ली। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 69.82 लाख रुपये का भुगतान कर नियामक मानदंडों के कथित उल्लंघन से संबंधित मामले को सेबी के साथ सुलझा लिया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया, कंपनी की मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियों की पुस्तकों तथा रिकॉर्ड के निरीक्षण के संबंध में सेबी को एक निपटान आवेदन प्रस्तुत किया। ये टिप्पणियां मुख्य रूप से एक मर्चेंट बैंकर के रूप में कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली उचित परिश्रम प्रक्रिया से संबंधित थीं। कंपनी सूचना के अनुसार, उसने सेबी के कारण बताओ नोटिस से उत्पन्न किसी भी लंबी कार्यवाही से बचने के लिए उपर्युक्त मामले के संबंध में निपटान विनियमों के तहत निपटान के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। भुगतान के बाद सेबी द्वारा पारित 20 अगस्त 2024 का निपटान आदेश कंपनी को उसी दिन मिल गया।

विनिर्माण क्षेत्र में बदलती भारत की तस्वीर

प्रहलाद सबनानी

भारत में आज भी देश की लगभग 60 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में निवास कर रही है और वह अपने रोजगार के लिए सामान्यतः कृषि क्षेत्र पर निर्भर है तथा देश की कुल अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान केवल 16-18 प्रतिशत के आसपास बना रहता है। अब यदि देश की 60 प्रतिशत आबादी देश के सकल घरेलू उत्पाद में केवल 16-18 प्रतिशत तक का योगदान दे पा रही है तो स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में गरीबी तो बनी ही रहेगी। परंतु, यह स्थिति अब धीरे धीरे बदल रही है क्योंकि हाल ही के वर्षों में भारत के विनिर्माण क्षेत्र का योगदान देश के सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों के नागरिक शहरी क्षेत्रों में स्थापित की जा रही विनिर्माण इकाइयों में रोजगार के नए अवसर प्राप्त करने के उद्देश्य से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। विनिर्माण क्षेत्र में कई ऐसे नए क्षेत्र भी उभरकर सामने आए हैं जिन क्षेत्रों में भारत में उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता रहा है। उदाहरण के लिए रक्षा क्षेत्र, दवा क्षेत्र, सेमी-कंडक्टर निर्माण क्षेत्र एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र आदि का वर्णन यहां प्रमुख रूप से किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में स्वदेशी रक्षा के क्षेत्र में उत्पादन की मात्रा 1.27 लाख करोड़ रुपए की रही है जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय 16.7 प्रतिशत अधिक है। यह भारत सरकार द्वारा देश में उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी नीतियों और सरकार के प्रयासों की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है। वर्तमान में रक्षा के क्षेत्र में उत्पादन करने वाली इकाईयों में सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों एवं निजी क्षेत्र की कम्पनियों

द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उक्त वर्णित उत्पादन में सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों का योगदान 79.2 प्रतिशत का रहा है जबकि निजी क्षेत्र की कम्पनियों का योगदान 20.8 प्रतिशत का रहा है।

हर्ष का विषय तो यह भी है कि रक्षा के क्षेत्र में भारत में निर्मित किए जा रहे उत्पादों की अन्य देशों में भारी मांग निर्मित होती जा रही है और इन उत्पादों का निर्यात भी लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 21,083 करोड़ रुपए के मूल्य का निर्यात भारत से विभिन्न देशों में किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 32.5 प्रतिशत अधिक है और यह भारत में रक्षा के क्षेत्र में हुए कुल उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत है। निर्यात में यह वृद्धि न केवल वैश्विक रक्षा बाजार में भारत के बढ़ते पदचिन्हों को दर्शाती है, बल्कि आत्मनिर्भरता और नवाचार के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत में विनिर्माण इकाईयों की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही के समय में कई रणनीतिक पहल भी केंद्र सरकार द्वारा की गई है, जैसे, मजबूत नीतिगत ढांचे को विकसित करना, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, अनुसंधान एवं विकास कार्यों में पर्याप्त निवेश को बढ़ावा देना, आदि शामिल हैं।

स्वदेशीकरण की नीति के अनुपालन का असर भी रक्षा के क्षेत्र में उत्पादन एवं निर्यात में हो रही भारी भरकम वृद्धि के रूप में दिखाई देने लगा है। रक्षा के क्षेत्र में उपयोग होने वाले सैकड़ों उत्पादों के आयात पर रोक लगाकर इन उत्पादों का उत्पादन भारत में ही करने के निर्णय का असर भी अब धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। रक्षा के क्षेत्र में विभिन्न उत्पादों का उत्पादन भारत में ही करने की नीति को लागू करने से देश में न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा बल्कि देश में आर्थिक प्रगति, तकनीकी उन्नति एवं रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा।

रक्षा क्षेत्र की तरह ही, हाल ही के समय में भारत ने उत्पादन के कई नए क्षेत्रों में प्रवेश किया है। कुछ वर्ष पूर्व तक दवा निर्माण के क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले एपीआई (ऐक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडीयंट) नामक कच्चे माल का लगभग पूरे तौर पर चीन से आयात किया जाता था।

क्रमशः ...

मुख्यमंत्री ने ई-आफिस प्रणाली, स्वागतम पोर्टल और मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाईन पोर्टल का किया शुभारंभ

शासकीय कामकाज को पारदर्शी बनाने और व्यवस्थित करने ई-आफिस प्रणाली की शुरुआत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और शासकीय काम-काज में पारदर्शिता लाने के लिए सभी क्षेत्रों में आईटी का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल शुरू हो गया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज तीन पोर्टलों ई-ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल और स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पहल से सुशासन के साथ शासकीय कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार सरकारी काम-काज में अधिक से अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अधिकाधिक क्षेत्रों में आईटी का उपयोग किया जा रहा है, ताकि भष्टाचार की गुंजाईश न रहे। मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर ये तीनों ऑनलाईन पोर्टल तैयार किए गए हैं, जिसका शुभारंभ आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में बटन दबाकर मुख्यमंत्री ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने मुख्य सचिव को सभी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के निर्देश देने संबंधी फाइल का डिजिटल अनुमोदन कर ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि सुशासन के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ई-आफिस प्रणाली और स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस और सरकारी काम में पारदर्शिता के उद्देश्य से सभी विभागों में आईटी के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। डिजिटल गवर्नेंस को हर स्तर पर ले जाने के लिए हम काम कर रहे है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आज हम लोगों ने सरकारी कामकाज में अधिक पारदर्शिता और आमजन की सुविधा के लिए एक साथ तीन-तीन ऑनलाइन प्रणाली का शुभारंभ किया है। तीनों पोर्टल का शुभारंभ प्रदेश में सुशासन स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगा। ई-ऑफिस प्रणाली से फाइलों के निराकरण में अनावश्यक देरी नहीं होगी। गलती की गुंजाइश कम होगी। फाइल किस स्तर पर है, इसकी ट्रेकिंग हो सकेगी।

इसी तरह मंत्रालय में मुख्यमंत्री, मंत्रीगणों और अधिकारियों से मिलने जो आंगतुक आते है, उनकी सुविधा के लिए स्वागतम पोर्टल भी शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने सीएमओ पोर्टल के शुभारंभ की जानकारी देते हुए बताया कि इसके माध्यम से सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों, जनहितैषी फैसलों और काम-काज की जानकारी आम लोगों को मिलेगी।

गौरतलब है कि ई-ऑफिस प्रणाली शुरुआती चरण में सामान्य प्रशासन विभाग में लागू किया गया है, जिसे क्रमशः सभी विभागों में लागू किया जाएगा। ई-आफिस प्रणाली में आफिस के दस्तावेज डिजिटल किये जाएंगे। दस्तावेज को एक आफिस से दूसरे आफिस भेजे जाने पर काफी समय लगता था, यह समय अब बच जाएगा। इसके साथ ही दस्तावेज में हेरफेर किये जाने की गुंजाईश समाप्त हो जाएगी। दस्तावेजों के खोने या गायब होने की दिक्कत नहीं रहेगी। डिजिटल माध्यम में दस्तावेज अधिक सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि अब तय समय-सीमा पर फाइलों का निराकरण हो सकेगा।

बाबू भैया की कलम से ✍

बलौदाबाजार हादसे में क्या इस तरह हो पायेगा समाधान

जब जब किसी घटी हुई घटना में उसकी दिशा बदलने वाला बयान आमने आता है। उस घटना का सच कभी बाहर नहीं आ पाता। वीभत्स झीरम हत्याकांड को ही ले लीजिए जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ अनेकों की हत्याऐं हुई।इस घटना में कांग्रेस के अग्रिम श्रेणी के लगभग सभी नेता मार दिए गए थे। प्रत्यक्षत: कहा गया कि यह नक्सलियों द्वारा की गई हत्याएं हैं। जिस तरह घटना घटी उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हुए। नक्सल घटना में किसी टारगेटेड नेता को मारने की बात कोई समझ सकता था। महेंद्र कर्मा उनके दुश्मन थे। उनसे बदला लिया गया होगा। उन्होंने स्वयं सरेंडर किया, कहा मझे मारो। बाकि किसी को कुछ मत करो। फिर भी बड़े नेताओं समेत कुल 30 लोग मारे गए। नंदकुमार के बड़े बेटे नये दिनेश पटेल को क्यों मारा गया,यह कोई समझ नहीं सका। यहीं पर घटना में शंकाएं उत्पन्न हुई। प्रभावित परिवारों को इस घटना में किसी राजनैतिक षड्यंत्र का आभास हुआ,उन्होंने घटना को षड़यंत्र के दृष्टिकोण से किसी बड़ी व निष्पक्ष जांच की मांग की।मांग के बाद कोई जांच बैठ पाती उसके पहले ही राजनैतिक दिशा बदलने की शक्ति रखने वालों ने राजनैतिक रूप से दिशा भटकने वाले बयान देने शुरू कर दिए थे। तत्काल बयान आ गया कि रमनसिंह ने ये हत्याएं करवाई हैं,यह रमन सरकार का षडयंत्र है। उच्चस्तरीय जांच होकर षडयंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए। दूसरे पक्ष ने भी जवाब में दिशा को और ज्यादा भटकाने का तुक्का फेंका, कहा कि बताएं अजित जोगी समय से पहले ही हेलिकॉप्टर से सभा स्थल से क्यों निकल गए। कवासी लखमा उनके कट्टर समर्थक नेता हैं, उन्हें पकड़ने के बाद भी बगैर कोई नुकसान पहुंचाएं क्यों छोड़ दिया। केंद्र ने जांच घोषित की जांच हुई। निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। सामान्य नक्सली घटना ही सामने आई। इस रिपोर्ट पर प्रभावित परिवारों को जरा भी भरोसा नहीं हुआ है। वे पूछ रहे हैं कि घटना स्थल पर मौजूद रहे तथा भुक्त भोगी घायल हुए अनेक अन्य नेताओं व नेताओं की सुरक्षा में लगे जवानों से पूछताछ किये बगैर कैसे जांच पूरी हो गई। उनका बयान क्यों नहीं लिया गया । अन्य राज्य जांच समितियों व आयोग ने जांच को सरकार की जगह, जांच अधिकारी ने नहीं उनके सहायक ने सीधे राज्यपाल के सुपुर्द कर प्रभावित परिवारों के मन में और संदेह को बढ़ा दिया। कुल मिलाकर देखें तो राजनैतिक बयानबाजी व प्रयासों के कारण घटना का असली सच आज तक सामने नहीं आ पाया है। आज भी बार बार यह बात अनेक मंचों पर उठ रही है। भाजपा, कांग्रेस पर और कांग्रेस, भाजपा पर उंगली उठा रही है। प्रभावित परिवारजन दोनों के बीच इस दिशा बदलने वाली राजनीति में उलझ कर अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस की तात्कालिक सरकार स्थानीय जांच एजेंसियों से जांच करने केंद्र सरकार की एजेंसी से फ़ाइल मांगते रह गई। सरकार ही चली गई लेकिन फ़ाइल नहीं मिली। झीरम के सच का आज भी सबको इंतजार है। अब ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य की भाजपा सरकार इस मामले को महत्व दे रही हैं। शायद अब यह मामला दम तोड़ता नजर आ रहा है। और यह हुआ दिशा बदलने वाले राजनैतिक बयानबाजी के कारण।

सम्भवत: देश में पहली बार घटी एक घटना हमारे ही प्रदेश में फिर घट गई। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुए। बलौदा बाजार जिला व पुलिस मुख्यालयों को उग्र भीड़ ने जलाकर खाक कर दिया। सैंकड़ों वाहनों को आग के हवाले कर दिया। अधिकारियों समेत सबने भाग कर अपनी अपनी जान बचाई। निरंकुश भीड़ ने वो सब कुछ किया, जो नहीं किया जाना चाहिए। देश भर में इस घटना से छत्तीसगढ़ की 'शांति का टापू' वाली साख को भारी बट्टा लगा। इस घटना से करोड़ों की सार्वजनिक सम्पति को बर्बाद कर दिया। कहा जा सकता है अपने ही घर को आग लगा दी घर के चिराग ने। यह घटना ऐसी जगह घटी जहां सतनामी समाज के बाबा गुरु घासी दास जीवन भर शांति सद्भाव के साथ रहने का संदेश देते थे। वे कहते थे 'मनखे मनखे एक समान' किसी में कोई भेदभाव नहीं है। । फिर कैसे यह अपवित्र घटना घटी। इसमें किसी को संदेह नहीं है कि मंच समाज की मांग के लिए बना था। अनेकों ने मंच से भाषण भी दिया, क्या दिया ,कैसे दिया ,किसने दिया सरकार के पास सब सबूत मौजूद हैं। कौन उस भीड में सतनामी समाज के थे, कौन बाहरी यह भी समझना सरकार के लिए कठिन नहीं था। लेकिन जिस तरह लोगों को जेलों में ठूंसा गया। अपनी निर्दोषिता का सबूत प्रस्तुत करने के बाद भी नहीं छोड़ा गया। इस बात ने फिर झीरम की तरह दिशा बदलने वाली राजनीति शुरू हो गई है

भाजपा संविधान बदलना, आरक्षण खत्म करना चाहती है: दीपक

रायपुर। भाजपा की केंद्र सरकार किसी ने किसी प्रकार से वंचित वर्गों का आरक्षण समाप्त करवाना चाहती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि देशभर के अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी वर्ग के लोगों को इस बात की आशंका है कि उनके आरक्षण को बाधित करने वर्ग भेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कोटा में कोटा भाजपा की साजिश है। देश भर के वंचित वर्ग के लोग मुखरता से भाजपा के साजिश के विरोध में सामने आये। आरक्षण पर आंच कदापि भी बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र देश विरोधी है, संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। क्रीमी लेयर के नाम पर आरक्षण को खत्म करने की एक बार फिर से साजिश भाजपा के इशारे में रची गई है। भाजपा के बांटने और काटने की नीति के तहत ही आरक्षित तबके के भीतर वर्गीकरण करके भेद पैदा करने की साजिश है, संविधान की मूल भावना के विपरीत आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कांग्रेस इसका विरोध करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है तब से आरक्षित वर्ग के हितों के खिलाफ़ फ़ैसले आ रहे हैं। भाजपा की सरकार है जानबूझकर न्यायलय में आरक्षित वर्गों का पक्ष नहीं रखती है। पहले तो सरकारी उपक्रमों के अंधाधुंध निजीकरण करके आरक्षित वर्ग के युवाओं का सरकारी नौकरी का अधिकार बेच दिया गया, अब बांकी बचे अधिकारों में भी क्रीमी लेयर का भेद? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि खास तौर पर भाजपा शासित राज्य और केंद्र के द्वारा लगातार आरक्षित वर्ग के युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। हाल ही में मोदी सरकार के द्वारा केंद्रीय सचिवालय में डायरेक्टर और अवर सचिव के पदों पर आरक्षण को दरकिनार कर लैटरल एंट्री का जो षड्यंत्र रचा था उसे कांग्रेस के दबाव में वापस लेना पड़ा। हाल ही मे उत्तर प्रदेश में जो 69000 शिक्षकों की भर्ती के जो परिणाम आए थे उसमें 27 परसेंट ओबीसी में से केवल 4 प्रतिशत को ही नियुक्ति मिली, इसी तरह से एससी और एसटी वर्ग के साथ भाजपा सरकार ने अन्याय किया था जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निरस्त करके भाजपा सरकार के षड़यंत्र को उजागर किया।

छत्तीसगढ़ में भी वंचित वर्ग का आरक्षण भाजपा ने रोका है

छत्तीसगढ़ में पढ़ने वाले बच्चों पर रहेगी अब शासन की सीधी नजर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए राजधानी रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में राज्य में एक और बड़ी पहल की गई है, जिसमें स्कूलों के साथ उनमें पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे के प्रदर्शन पर भी अब सीधी नजर रखी जाएगी। सॉफ्टवेयर एवं मोबाइल एप्प का विकास तथा कॉल सेंटर के माध्यम से मॉनिटरिंग आई.आई.टी. भिलाई के सहयोग से किया जा रहा है।

स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की ऑनलाईन मॉनिटरिंग एवं आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए रायपुर स्थित पेंशन बाड़ा में विद्या समीक्षा केन्द्र की स्थापना की गई है। इस केन्द्र के माध्यम से शासन की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू एवं मॉनिटरिंग करने में आसानी होगी। स्कूल और उनमें पढ़ने वाले एक-एक बच्चों के प्रदर्शन का रीयल टाइम ब्यौरा मुहैया कराएगा।

विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना से शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित जानकारी एवं सुविधाओं को विद्यार्थियों, पालकों एवं शिक्षकों तक आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। शालाओं में मूलभूत संरचनाओं की उपलब्धता, मरम्मत, उपयोगिता आदि की सतत् मॉनिटरिंग की जायेगी ताकि विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए उचित एवं पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो सके तथा बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सके।

इसके द्वारा शिक्षकों की पदस्थापना से संबंधित जानकारियों की भी मॉनिटरिंग की जा रही है।

विद्या समीक्षा केन्द्र के अंतर्गत शिक्षकों का विवरण, यूडाइस डाटा, मध्यान्ह भोजन, शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित मॉनिटरिंग, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति, अधिकारियों के द्वारा शालाओं का निरीक्षण, विद्यार्थियों का मूल्यांकन आदि तथा केन्द्र सरकार से सबद्ध शैक्षिक योजनाओं की नियमित आनलाइन मानिटरिंग की जायेगी। योजनाओं की मॉनिटरिंग हेतु साफ्टवेयर एवं एप्प भी तैयार किया जा रहे हैं। योजनाओं की मॉनिटरिंग हेतु काल सेंटर स्थापित किया गया है। विद्यार्थियों, पालकों एवं शिक्षकों की शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिये एक टोल-फ्री नम्बर भी जारी किया जायेगा। स्कूल में मूलभूत सुविधाएँ जैसे शाला भवन, शौचालय, विद्युत् व्यवस्था आदि उपलब्ध है अथवा नहीं है, के सबंध में एआई आधारित माड्यूल के उपयोग से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

प्रमुख समाचार छत्तीसगढ़/राजधानी

सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही: कांग्रेस

रायपुर। महादेव एप्प मामले की जांच सीबीआई से करवाने की गृहमंत्री के घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह भाजपा का नया राजनैतिक प्रोपोगंडा है। गृहमंत्री द्वारा महादेव एप्प मामले की सीबीआई जांच की बात करना यह भी बताता है कि गृह मंत्री को राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं है। जिस विभाग के वे मुखिया है उनको उसी विभाग पर भरोसा नहीं है। जिस प्रकार से राज्य में अपराध बढ़े है तथा प्रदेश की कानून व्यवस्था बदतर हुई है 8 माह में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है उससे गृहमंत्री को भी समझ आने लगा है कि उनकी पुलिस नाकाबिल है इसीलिये वे सीबीआई जांच की बात करते है। गृहमंत्री सीबीआई जांच की बात करके अपनी सरकार की अक्षमता को छुपा नहीं कसते। अपराध रोकना पुलिस का मूल काम है। राज्य सरकार की पुलिस इसमें फेल साबित हुई है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पहले ईडी ने जांच किया, ईओडब्ल्यू ने जांच किया। अब गृहमंत्री सीबीआई जांच की बयानबाजी यह बताती है कि भाजपा सरकार इस मामले में सिर्फ अवसरवादी राजनीति कर रही है।

रक्षाबंधन के त्यौहार में भी बहनें सुरक्षित नहीं - वंदना राजपूत

रायपुर। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता वंदना राजपूत ने बढ़ती महिला अपराधों पर भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि कुशासन के सरकार में रक्षाबंधन की पवित्र दिन भी बहनें सुरक्षित नहीं है रायगढ़ में राखी बांधने आई महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना पूरी मानव जाति को शर्मसार करने वाली घटना है इस सामूहिक दुष्कर्म की घटना यह सिद्ध करता है कि प्रदेश में कानून का डर अपराधियों के दिलों दिमाग में रति भर भी नहीं है कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की 8 महीना की सरकार में महिलाओं के प्रति अपराध के 2000 से अधिक मामलें दर्ज हुये है। लगभग 170 से अधिक गैंगरेप और 500 से अधिक बलात्कार की घटनाएं घटी है। आदिवासी मुख्यमंत्री होकर भी आदिवासी महिला की अस्मिता को बचाने में नाकाम रहे हैं लगातार आदिवासी महिलाओं की अस्मिता को लूटा जा रहा है तो तभी आदिवासी महिलाओं को गोली से भूना जा रहा है। वंदना राजपूत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डबल इंजन की सरकार में महिला अपराध की लगातार बढ़ती घटना ने सरकार की पोल खोल रखी है लगातार बेटियों के साथ गैंगरेप बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है साय सरकार बेटियों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है आज बेटियां ना घर में सुरक्षित है और ना ही बाहर सुरक्षित है आज छत्तीसगढ़ की स्थिति को देखकर के अन्य राज्य से महिलाएं छत्तीसगढ़ आने से डर रही है।

नक्सल मामले में राज्य के गृह मंत्री असफल

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि नक्सल मामले में राज्य के गृह मंत्री असफल हैं इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री बैठक लेने आ रहे हैं। राज्य के गृह मंत्री कभी कहते हैं कि नक्सलियों से फोन पर चर्चा करेंगे कभी नक्सलियों से आन लाईन सुझाव मांगते हैं। गृहमंत्री को समझ नही आ रहा है कि नक्सलवाद को खत्म करने कैसे योजनाबद्ध काम करे? सरकार के ढुल मूल रवैया के चलते ही नक्सली एक बार फिर पैर पसार रहे हैं। भाजपा सरकार बनने के बाद नक्सली आतंक बढ़ा है। 8 महीने में सरकार नक्सलवाद को लेकर कोई ठोस नीति या योजना नहीं बना पायी। नक्सली हमले में निर्दोष लोगों की जाने जा रही है जवान शहीद हो रहे हैं। नक्सलवाद खत्म करने के मोर्चे पर पूरी तरीका से सरकार विफल हो गई है प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के दौरान नक्सलवाद को खत्म करने के लिए विश्वास विकास और सुरक्षा के नीति पर काम किया गया था। नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जनता से सुझाव लेकर नक्सल मोर्चे पर काम किया गया था जिसका ही परिणाम है कि नक्सली वारदात में 68 प्रतिशत की कमी आई थी। बीहड़ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय बटालियन के तैनातियों की गई।

मौत के 4 साल बाद पीड़िता को मिला इंसाफ

रायपुर। राजधानी के आरंग इलाके में युवती का यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना के मामले में रायपुर सेशन कोर्ट ने 3 आरोपियों को दो-दो हजार रूपये अर्थदंड और दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है। पीड़िता ने मई 2020 में आरोपियों द्वारा किए गये यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। बता दें कि आरोपियों का नाम करण देवांगन, इशु मिरी, परमेश्वर चक्रधारी है, तीनों आरंग के ग्राम समेदा के रहने वाले है. तीनों आरोपियों ने पीड़िता के कुछ निजी फोटो उतार लिए थे, जिसके बाद उसे वायरल करने की धमकी देकर वह पीड़िता का यौन उत्पीड़न करने लगे इस बात से युवती काफी परेशान थी और उसने प्रताड़ना और बदनामी के डर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद मृतिका के परिजनों ने आरंग पुलिस थाने जाकर मामला दर्ज कराया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 306, 34 भादंसं का अपराध दर्ज तत्काल कार्रवाई शुरू की और उन्हें धर दबोचा और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। इसके बाद करीब 4 साल तक मामले में सुनवाई हुई और अब जाकर पीड़िता को इंसाफ मिला है। तीनों आरोपियों को कोर्ट ने 2-2 हजार रूपये अर्थदंड और 6 माह के श्रश्रम कारावास समेत 10-10 साल की सजा सुनाई है। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक राघवेंद्र सिंह ने मामले की पेरवी की।

लाखों की ठगी करने वाले गिरोह की महिला सदस्य गिरफ्तार

रायपुर। न्यायधानी के सिरगिट्टी इलाके में 30 लाख की ठगी करने वाली दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है, ये महिलाएं खुद को काइम ब्रांच का अधिकारी बताकर चोरी की वारदातों को अंजाम देती थीं। पुलिस ने इन महिलाओं के कब्जे से 30 लाख नकद बरामद किया है, वहीं गिरोह से जुड़े 4 अन्य युवकों की तलाश की जा रही है। बता दें कि बीते 14 अगस्त को काली मंदिर तिफरा के पास रहने वाले कृष्ण कुमार मिश्रा ने सिरगिट्टी थाने में रिपोर्ट लिखाई कि बीते 13 अगस्त की रात्रि करीब 9 बजे वह राजनांदगांव से वापस घर आया तो पता चला कि दोपहर 12 से 1 बजे के बीच 4 पुरुष और 2 महिला घर में घुस गये और उन्होंने खुद को काईम ब्रांच आफिसर होना बताया। इस दौरान सभी ने गले में परिचय पत्र लटकाये हुये थे और घर में महिलाओं को यहां से हिलोगे तो तुम्हे जान से मार देगें कहकर धमकी दे रहे थे। फिर उनके घर में सकरी निवासी विधा प्रकाश पाण्डेय द्वारा रखवाई गई पेटी को ढूंढने लगे और मिलने पर उसे लेकर भाग निकले। यह सुनने के बाद कृष्ण कुमार मिश्रा ने विधा प्रकाश पाण्डेय को फोन कर इसकी जानकारी दी, तो विधा प्रकाश पाण्डेय बताया कि पेटी के अंदर पैसा एवं जमीन संबंधी कागजात रखा हुआ था। जिसकी जानकारी होने पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपियों को तलाशने शहर में लगे 300 से अधिक सी.सी.टी.वी. फुटेज खंगाले, जिससे संदिग्धों का हुलिया एवं वाहन की बारिक जानकारी प्राप्त हुई।

समितियों को प्रदेशव्यापी स्वरूप देंगे पैक्स का विस्तार किया जाएगा: कश्यप

कांग्रेस सरकार ने सहकारिता क्षेत्र की दुर्दशा की थी उसे सुधार कर फिर प्रभावी बनाना है: किरण देव

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ की एक प्रदेश स्तरीय बैठक बुधवार को भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में हुई। बैठक में जिला संयोजक और प्रभारी उपस्थित रहे। बैठक में पंचायतों में पैक्स का विस्तार और कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मार्केटिंग सोसाइटियों के उन्नयन और मत्स्य नीति में संशोधन पर भी चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश सहकारिता और वन मंत्री केदार कश्यप, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय का मार्गदर्शन मिला।

बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि सहकारिता का विषय बहुत व्यापक है। सहकार से समग्र विकास की कल्पना प्रधानमंत्री श्री मोदी और केन्द्रीय मंत्री श्री शाह ने की है। इसमें सहकारिता को बहुउद्देश्यीय स्वरूप दिया जा रहा है। केन्द्रीय

गृह व सहकारिता मंत्री श्री शाह ने देश में पैक्स के विस्तारीकरण पर बल दिया है। इस दृष्टि से सरकार के साथ ही सहकारिता प्रकोष्ठ का दायित्व ज्यादा गंभीर है। कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में सहकारिता क्षेत्र की जो दुर्दशा की थी, उसे सुधारकर सहकारिता के क्षेत्र को पुन: प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य करना है। श्री देव ने मोर्चों के साथ-साथ प्रकोष्ठों की प्रभावी भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि जिलाध्यक्षों के साथ चर्चा करके पैक्स के विस्तारीकरण की रूपरेखा तय करें। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की उपज आदि बिन्दुओं पर ध्यान देना होगा। इसके लिए जिला स्तर के सहकारिता प्रकोष्ठों को भी सक्रिय होना होगा। इस विषय को गंभीरता से लेकर योजनापूर्वक काम करना होगा। इसकी कार्ययोजना बनाने के लिए जिला व मंडल स्तर तक चर्चा की जाए। सहकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले सभी लोगों का मार्गदर्शन व सहयोग लेना चाहिए। हर पंचायत में वर्कआउट करना होगा और हर पंचायत में पहुंचना होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जिस आर्थिक सशक्तिकरण की परिकल्पना की है, वह इससे भली प्रकार साकार होगी।

बैठक को संबोधित करते हुए सहकारिता व वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पूरे देश में पैक्स का विस्तार करना है, यह 13 अगस्त को दिल्ली में हुई बैठक में तय हुआ है, इसलिए प्रदेश में हमें पैक्स का विस्तार करके प्रदेश की सभी पंचायतों में सहकारिता का प्रभाव बढ़ाएं। केन्द्रीय मंत्री अमित शाह के आगामी छत्तीसगढ़ प्रवास की चर्चा करते हुए श्री कश्यप ने कहा कि सन् 2047 तक देश में सरकार हो, इसलिए सहकारिता के क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देना होगा। प्रदेश सरकार भी सहकारिता के क्षेत्र में नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए सतत चिंतनशील है।

भोरमदेव महोत्सव से पहले वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्य पूर्ण कराये-उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा

रायपुर. उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज अपने निवास कार्यालय में संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग तथा कबीरधाम जिले से आये गणमान्य नागरिकों एवं पुजारी के साथ भोरमदेव मंदिर के जीर्णोद्धार के संबंध में बैठक ली। बैठक में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं को बढ़ाने और मंदिर परिसर के विकास के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि बरसात के दिनों में पानी रिसाव की समस्या को तत्काल दूर करे। उन्होंने संस्कृति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि मंदिर के इतिहास से संबंधित वीडियो डॉक्यूमेंटेशन बनाये ताकि श्रद्धालु मंदिर के इतिहास से परिचित हो सके। उन्होंने श्री डी डिजाइन और लिडार सर्वे करवाने के निर्देश भी दिए। साथ ही भोरमदेव महोत्सव से पहले वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्य और ट्रीटमेंट को पूरा करने के निर्देश दिए।बैठक में संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संचालक श्री विवेक आचार्य, सहायक अभियंता श्री चेतन मनहरे, उप अभियंता श्री दिलीप साहू, कबीरधाम क्षेत्र के श्री आदित्य श्रीवास, अजय चंद्रवंशी, आशीष पाठक, अमित वर्मा, दुर्गेश दुबे एवं खोरु सिंह उपस्थित थे। बैठक में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं को बढ़ाने और मंदिर परिसर के विकास के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई।श्रद्धालुओं के लिए शेड का निर्माण, चौकीदार क्वाटर को मंदिर के पास से अन्यत्र शिफ्ट करने तथा मंदिर के पीछे वीआईपी रूम बनाने चर्चा की गई। इसके अलावा मंदिर के पीछे और वीआईपी रूम के बीच की दीवाल को हटाकर ग्रील और गेट लगाने, भैरव मंदिर, चामुंडा माता

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.